

अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावनाएं

1

अध्याय

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण आई मंदी से उल्लेखनीय तीव्रता के साथ सुधार हुआ है। 31 जनवरी, 2011 को जारी त्वरित अनुमानों द्वारा 2009-10 की अब 8.0 प्रतिशत पर अनुमानित वृद्धि तथा 7 फरवरी, 2011 को जारी केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2010-11 में अनुमानित 8.6 प्रतिशत की वृद्धि से यह क्रमावर्तन अत्यंत तेजी से तथा सशक्त रूप से हुआ है। कृषि में पुनः सुधार तथा विनिर्माण में सतत् संवेग के साथ वर्ष 2010-11 में संवृद्धि सशक्त थी (अग्रिम अनुमानों के अनुसार), अलबत्ता मुख्यतः समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं में गिरावट के कारण सेवा क्षेत्र में गिरावट हुई जो विगत दो वर्षों में राजकोषीय प्रेरण के मूल प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है। नवम्बर तथा दिसम्बर 2010 से संबंधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा यथा निर्दिष्टानुसार विशेष रूप से उद्योग और विनिर्माण में आई गिरावट कुछ चिंता का विषय है। तथापि, औद्योगिक निष्पादन के अन्य संकेतकों में उत्प्लावकता तथा आईआईपी मंदी का अल्पकालिक स्वरूप सुझाता है कि यह हास किसी दीर्घ कालिक समस्या के संकेत के बजाए आवसरिक गिरावट के स्वरूप का है। औद्योगिक क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था की मध्यम से दीर्घावधिक संभावना, सकारात्मक बनी हुई है। मांग पक्ष पर, बचतों तथा निवेश में वृद्धि तथा निजी खपत में तेजी वर्ष 2010-11 में 9.7 प्रतिशत पर सतत् बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की सशक्त वृद्धि में परिणामी हुई है। मौद्रिक समायोजन का अनुवर्ती तथा क्रमिक रूप से वापस लिया जाना मुद्रास्फीतिकारी दबावों के सृजन को नियंत्रित करने में सहायता कर रहा है। वर्तमान राजकोषीय वर्ष के अधिकांश समय बढ़े हुए स्तर पर बनी रहीं मुद्रास्फीति अधिकांशतः खाद्य मदों द्वारा चालित थी, यद्यपि राजकोषीय वर्ष के आरम्भ में मुद्रास्फीतिकारी वस्तुएं उन वस्तुओं से भिन्न थी जिनकी कीमतें अब बढ़ रही हैं। घट-बढ़ के झटकों वाले तंग होते मुद्रा बाजारों और जमाराशियों में संतुलित वृद्धि के बावजूद ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी, उत्साहशील इक्विटी बाजारों, स्थिर विदेशी मुद्रा बाजारों के चलते वित्तीय स्थिति सुव्यवस्थित बनी हुई है। नवीनतम मासिक पण्य वस्तु व्यापार आंकड़ों के अनुसार आयातों में कमी तथा निर्यातों में त्वरण के साथ भुगतान संतुलन के चालू खाते में संतुलन संभावित है। यद्यपि वैश्विक घटनाओं, विशेषतया कच्चे तेल जैसी वस्तु कीमतों (मध्य पूर्व में राजनैतिक गड़बड़ द्वारा वर्धित) के अधोमुखी जोखिम बने हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था वृहद् आर्थिक संकेतकों के अर्थ में और सुधरने तथा सुदृढ़ होने के लिए तत्पर है।

1.2 यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि तत्काल पूर्ववर्ती विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र अनुक्रम में दो आघातों से गम्भीर अवमंदन आया है जिनको इसने सफलतापूर्वक झेला है:- क) वर्ष 2007-09 में वैश्विक संकट के छाने के साथ विश्व वृद्धि, वित्त तथा व्यापार का ध्वंसन जिसके अवशिष्ट प्रभाव वर्ष 2009-10 में जारी रहे तथा 2010-11 में भी (यूरोप में राजकोषीय दबाव के साथ) उनका प्रभाव बना रहा; तथा (ख) घरेलू रूप से, अनिश्चित मानसून 2008-09 में कृषि

तथा संबद्ध क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2009-10 में गम्भीर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और बेमौसमी विलम्बित वर्षा ने 2010-11 में शीत ऋतु की फसलों को प्रभावित किया।

1.3 आर्थिक दबाव की यह अवधि नागरिकों तथा नीतिनिर्माताओं दोनों के लिए एकसमान परीक्षा की अवधि रही है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सौम्यता, शांति तथा सुदृढ़ता से सुधार हो रहा है। हालांकि कुछ बादल छाये हुए हैं-जैसे निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति तथा औद्योगिक वृद्धि में अस्थायी मंदी समग्र वृद्धि में

0.1 मुख्य संकेतक

आंकड़ा श्रेणियां और संघटक	यूनिट	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1. स.घ.उ. और संबंधित संकेतक							
स.घ.उ. (वर्तमान बाजार मूल्य)	₹ करोड़	3692485	4293672	4986426	5582623 ^{अन.अ.}	6550271 ^{त्व.अ.}	7877947 ^{अ.अ.}
वृद्धि दर	%	13.9	16.3	16.1	12.0	17.3	20.3
स.घ.उ. (घटक लागत 2004-05 के मूल्य पर)	₹ करोड़	3254216	3566011	3898958	4162509 ^{अन.अ.}	4493743 ^{त्व.अ.}	4879232 ^{अ.अ.}
वृद्धि दर	%	9.5	9.6	9.3	6.8	8.0	8.6
बचत दर	स.घ.उ. का %	33.5	34.6	36.9	32.2	33.7	उन
पूँजी निर्माण (दर)	स.घ.उ. का %	34.7	35.7	38.1	34.5	36.5	उन
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर उपादान लागत)	₹	27123	31198	35820	40605	46492	54527
2. उत्पादन							
खाद्यान्न	मिलियन टन	208.6	217.3	230.8	234.5	218.1 ^क	232.1 ^ख
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक ^ग (वृद्धि)	प्रतिशत	8.0	11.9	8.7	3.2	10.5	उन
विद्युत उत्पादन (वृद्धि)	प्रतिशत	5.2	7.2	6.4	2.8	6.0	उन
3. कीमतें							
मुद्रास्फीति (थो.मू.सू.) (12 माह औसत)	% परिवर्तन	4.3	6.5	4.8	8.0	3.6	9.4 ^ध
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू) (औसत)	% परिवर्तन	4.4	6.7	6.2	9.1	12.4	11.0 ^ध
4. वैदेशिक क्षेत्र							
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	23.4	22.6	29.0	13.6	-3.5	29.5 ^झ
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	33.8	24.5	35.5	20.7	-5.0	19.0 ^झ
चालू खाता घाटा (सीएडी)/स.घ.उ.	प्रतिशत	-1.2	-1.0	-1.3	-2.3	-2.8	उन
विदेशी मुद्रा भण्डार	बिलियन अमरीकी डालर	151.6	199.2	309.7	252.0	279.1	297.3 ^च
औसत विनिमय दर	₹/अमरीकी डालर	44.27	45.25	40.26	45.99	47.42	45.68 ^छ
5. मुद्रा तथा ऋण							
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	16.9	21.7	21.4	19.3	16.8	16.5 ^ज
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	% परिवर्तन	30.8	28.1	22.3	17.5	16.9	24.4 ^ज
6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)							
सकल राजकोषीय घाटा	स.घ.उ. का %	4.0	3.3	2.5	6.0	6.3 ^झ	4.8
राजस्व घाटा	स.घ.उ. का %	2.5	1.9	1.1	4.5	5.1 ^झ	3.5
प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. का %	0.4	-0.2	-0.9	2.6	3.1 ^झ	1.7
7. जनसंख्या	मिलियन	1106	1122	1138	1154	1170	1186
(1 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार वर्षवार अनुमानित जनसंख्या)		(2005)	(2006)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)

अ.अ वर्ष 2010-11 के लिए स.घ.उ. आंकड़े अग्रिम अनुमान हैं; अन.अनु अंतिम अनुमान त्व.अ. त्वरित अनुमान

उन अभी उपलब्ध नहीं/ 2009-10 के लिए जारी

क अंतिम अनुमान

ख द्वितीय अग्रिम अनुमान

ग वार्षिक संवृद्धि दरें वर्ष 2005-06 से पुनः संकलित की गई हैं क्योंकि सूचकांक मूल्य अर्थों में सूचित आईआईपी मदों के लिए थोक मूल्य सूचकांक की नवीन श्रृंखला का प्रयोग करके अप्रैल 2004 से पुनः संकलित किए गए हैं।

घ औसत अप्रैल-दिसम्बर 2010

ड अप्रैल-दिसम्बर 2010

च 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार।

छ 2010-11 के लिए औसत विनिमय दर (अप्रैल-दिसम्बर 2010)।

ज अंतिम।

झ 2009-10 के लिए राजकोषीय संकेतक 2009-10 के लिए अंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं।

गत्यात्मकता सुस्पष्ट है क्योंकि अनेक समाज संरक्षण उपायों ने आघातों को सहने की क्षमता को पर्याप्त सशक्त बना दिया है। ये परिणाम प्रति-चक्र्रीय वृहद् आर्थिक नीतियों, संवृद्धि को संवर्धित करने के संरचनात्मक उपायों, निर्धनों के संरक्षण हेतु अपेक्षाकृत सशक्त आधार की व्यवस्था करने हेतु सामाजिक व्यय के कारण तथा जैसाकि आर्थिक प्रगति में सदैव होता है, किंचित सौभाग्य के कारण है। सौभाग्य अच्छे मौसम के रूप में तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के धीमे किन्तु सुस्थिर सुधार के रूप में आया। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में, इस संकट के दौरान भारी प्रगति हुई तथा भविष्य के लिए मूल्यवान पाठ सीखे गए।

1.4 वर्ष 2010-11 में घटक लागत (वास्तविक संघ०उ०) पर सतत् 2004-05 कीमतों पर संघ०उ० में वृद्धि के अनुमानित स्तर का संघटन यह था: कृषि में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि जिसमें विगत वर्ष में हास की तुलना में वापस उछाल आया; उद्योग में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि जिसकी वृद्धि दर वर्ष 2009-10 में 8.0 प्रतिशत थी; तथा सेवाओं की वृद्धि में हास जिनकी वृद्धि दर वर्ष 2009-10 में 10.1 प्रतिशत के स्तर की तुलना में 9.6 प्रतिशत थी (सारणी 1.1)। मांग पक्ष पर, सतत् कीमतों 2004-05 पर संघ०उ० के बाज़ार कीमतों पर 9.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। हालिया वृहद् आर्थिक आंकड़ों से चार सुभिन्नकारी कारक उभरते हैं। प्रथम, सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं पर आधारिक प्रभाव के लिए समायोजित, सेवा क्षेत्रक, जिसका वर्ष 2009-10 में 57.3 प्रतिशत का अंश था, ने अंततः संवेग हासिल करना आरम्भ कर दिया है तथा इस तथ्य को देखते हुए कि यह भारतीय वृद्धि का पारम्परिक पावर हाऊस रहा है, मध्यावधिक संभावनाओं की उच्च प्रत्याशा को दर्शाता है। दूसरे, बचत दर बढ़कर 2009-10 में संघ०उ० के 33.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है तथा निवेश दर 36.5 प्रतिशत तक है जो लगभग 4 के वर्धनात्मक पूंजी-उत्पादन अनुपात को देखते हुए स्थायी उत्पादन वृद्धि की संभावनाएं निर्दिष्ट करती हैं। तीसरे, हालिया मासिक आईआईपी आंकड़ों के अनुसार, उद्योग में उल्लेखनीय हास हुआ है, आयातों में गिरावट आई है तथा मुख्य मुद्रास्फीति के चिह्न मध्य पूर्व में भू-राजनैतिक जोखमों के

चलते उच्च स्तरों पर बने हुए हैं। इन सब के संवेग को मंद करने के निहितार्थ हो सकते हैं चाहे ऐसा अल्पावधि में ही हो। चौथे, राजकोषीय नीति समेकन पथ पर अग्रसर है जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप में उछाल के कारण राजस्व का निष्पादन अच्छा हो रहा है तथा भविष्य में इस के द्वारा एक वास्तविक चक्र को गतिशील बनाते हुए मध्यम से दीर्घावधि में वृद्धि लाभांश प्राप्त होने की संभावना है।

1.5 थोक मूल्य सूचकांक द्वारा यथामापित वर्षानुवर्ष प्रमुख मुद्रास्फीति दिसम्बर 2009 से उच्च स्तरों पर बनी हुई है यद्यपि यह कुल मिलाकर अप्रैल 2010 से अधोमुखी पथ पर अग्रसर है जब थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्षानुवर्ष 11 प्रतिशत की चरम सीमा पर थी। जनवरी 2011 में मुद्रास्फीति 8.23 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष निर्माण (मार्च 2010 से) जनवरी 2011 तक 7.44 प्रतिशत पर बना रहा। प्राथमिक वस्तुओं, विशेषतया खाद्य मदों में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के उच्च स्तरों में मुख्य योगदाता थी। घटते मूल प्रभाव के साथ, नवम्बर 2010 में समग्र थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में क्रमिक संतुलन आया जब इसे 7.48 प्रतिशत आंका गया; दिसम्बर 2010 में पुनः वृद्धि हुई जो मुख्यता कतिपय खाद्य मदों (फल तथा सब्जियां, दूध, अंडे, मांस और मछली) तथा साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों द्वारा संचालित थी। संरचनात्मक तथा वृहद् आर्थिक, दोनों क्षेत्रों में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति से जूझने के लिए अनेक उपाय किए गए।

1.6 कीमतों संबंधी साप्ताहिक आंकड़ों के आधार पर, खाद्य मदों में मुद्रास्फीति 5 जून 2009 से 76 सप्ताह के लिए द्विअंकीय बनी रही; 20 नवम्बर 2010 तथा 4 दिसम्बर 2010 के बीच तीन सप्ताहों के लिए लघु समय तक द्विअंकीय स्तर से नीचे रहने के पश्चात यह पुनः द्विअंकीय हो गई और 22 जनवरी 2011 को मुद्रास्फीति बढ़कर 17.05 प्रतिशत हो गई थी। 15 जनवरी 2010 तथा 19 जून 2010 के बीच, यह 23 सप्ताहों में से 22 सप्ताह 20 प्रतिशत से उच्च बनी हुई थी। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष भी उच्च बनी रही थी, इस वर्ष उच्चतर मुद्रास्फीति का संघटन भिन्न था; पिछले वर्ष मुद्रास्फीति के मुख्य चालक दालें, अनाज तथा चीनी

सारणी 1.1 : 2004-2005 कीमतों पर घटक लागत पर स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 ^{अ.अ.}	2009-10 ^{त्व.अ.}	2010-11 ^{अ.अ.}
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	5.1	4.2	5.8	-0.1	0.4	5.4
खनन तथा उत्खनन	1.3	7.5	3.7	1.3	6.9	6.2
विनिर्माण	10.1	14.3	10.3	4.2	8.8	8.8
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	7.1	9.3	8.3	4.9	6.4	5.1
संरचना	12.8	10.3	10.7	5.4	7.0	8.0
व्यापार, होटल, परिवहन, तथा संचार	12.1	11.7	10.7	7.6	9.7	11.0
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं	12.7	14.0	11.9	12.5	9.2	10.6
समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	7.0	2.9	6.9	12.7	11.8	5.7
घटक लागत पर कुल संघ०उ०	9.5	9.6	9.3	6.8	8.0	8.6

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

थे जिनकी मूल्यवृद्धि मानसूनी कमी पर आरोप्य की जा सकती है जबकि इस वर्ष यह उच्चतर आपूर्ति स्तरों के बावजूद मांग कारकों द्वारा संचालित प्रतीत होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों द्वारा यथा मापित मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य मदों को अपेक्षाकृत अधिक भारांश समनुदेशित किए जाते हैं, तीव्रता से बढ़कर जनवरी 2010 में चरम स्तरों पर पहुंच गई; तत्पश्चात यह थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में घट बढ़ के अनुरूप मोटे तौर पर संतुलित हो गई है।

1.7 घरेलू क्षेत्र में मुद्रास्फीतिकारी दबावों के वैश्विक वस्तु कीमतों के उच्चतर स्तरों द्वारा त्वरित होने की संभावना है तथा इसका कारण सहज मुद्रा नीति भी है जिसका अनुसरण अपनी स्वयं की अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहे अनेक औद्योगिक राष्ट्रों में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पूर्वानुमान (जनवरी 2011 के वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अपडेट, के अनुसार) सतत् मजबूत मांग तथा कठोर बाजार दशाओं के प्रति मंद आपूर्ति अनुक्रिया के जरूरी रहने के कारण वर्ष 2011 में उदीयमान तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्च उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति के जारी रहने की संभावना निर्दिष्ट करते हैं। आईएमएफ ने पैट्रोलियम कीमतों के लिए अपने आधार रेखा पूर्वानुमान को भी डब्ल्यूईओ अक्टूबर 2010 में 79 अमरीकी डालर/बीबीएल से बढ़ाकर डब्ल्यूईओ के जनवरी अपडेट में 90 अमरीकी डालर/बीबीएल कर दिया है। तेल-भिन्न वस्तु कीमतों में वर्ष 2011 में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अपडेट में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि अधिकांश वस्तु श्रेणियों के लिए निकटावधि जोखिम अब अधिक हैं तथा कुछ उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जो तेजी से विकसित हुई थी, उत्पादन कमियों की समाप्ति के कारण अधिक तेजी आने का जोखिम विद्यमान है।

1.8 आईएमएफ ने वैश्विक वृद्धि अनुमानों में उर्ध्वमुखी संशोधन किया है जिसे अब 2011 में 4.4 प्रतिशत आंका गया है। वर्ष 2010 में 9.7 प्रतिशत (सतत् बाजार कीमतों पर स०घ०उ० के अर्थ में) की वृद्धि के पश्चात वर्ष 2011 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। आधारीक परिदृश्य के अंतर्गत जिसमें यूरो क्षेत्र में वित्तीय अस्तव्यस्तता से संसर्ग नियंत्रित है, उदीयमान बाजार पूंजी अंतर्वाहों के सशक्त बने रहने तथा वित्तीय दशाओं के मजबूत बने रहने की आशा है। अपडेट के अनुसार उदीयमान बाजारों के लिए मुख्य जोखिम अतित्वरण, मुद्रा-स्फीतिकारी दबावों की तीव्र वृद्धि तथा एक कठोर अवतरण की संभावना से संबंधित है।

आर्थिक घटनाक्रमों की समीक्षा

वृद्धि व्यापकाधारित, सुधार ठोस पथ पर

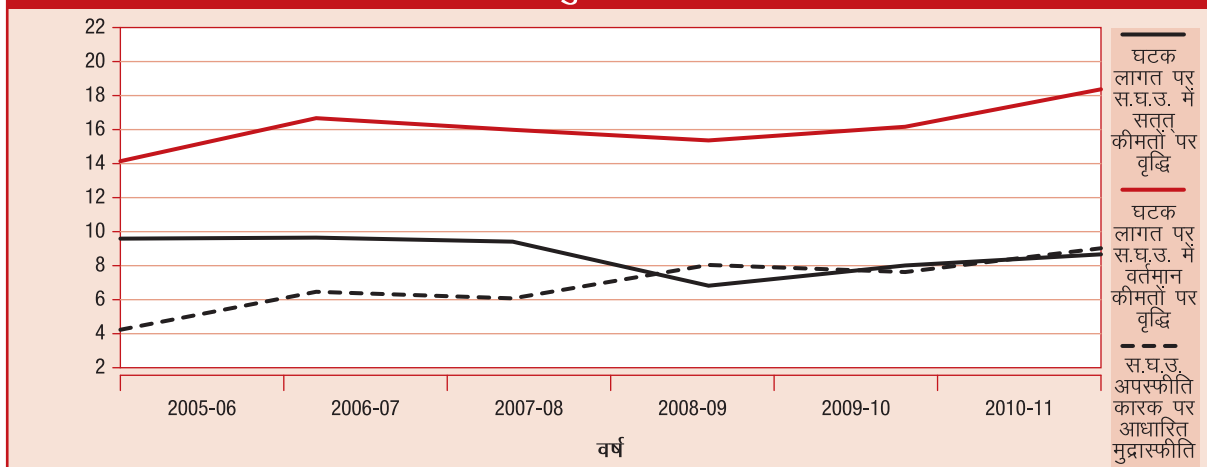
1.9 सीएसओ ने 31 जनवरी 2011 को जारी अपने त्वरित अनुमानों में वर्ष 2009-10 के लिए वास्तविक स०घ०उ० में वृद्धि को

7.4 प्रतिशत से संशोधित करके 8.0 प्रतिशत किया है। (इन संशोधनों में आधार वर्ष 2004-05 को मानते हुए डब्ल्यूपीआई की नवीन श्रृंखला तथा साथ ही आईआईपी में अनुवर्ती संशोधन को ध्यान में रखा गया है)। वर्ष 2008-09 के लिए वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि भी संशोधित होकर 6.8 प्रतिशत आंकी गई है (0.1 प्रतिशतांक अधिक)। संघटनात्मक रूप से, स०घ०उ० में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो त्वरित अनुमानों के अनुसार कृषि में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि (संशोधित अनुमानों के अनुसार 0.2 प्रतिशत); उद्योग में संशोधित अनुमानों में 9.3 प्रतिशत की तुलना में 8.0 प्रतिशत का वृद्धि स्तर तथा सेवाओं की वृद्धि में 10.1 प्रतिशत की अपेक्षाकृत तीव्र बढ़ती दर्शाते हैं जबकि संशोधित अनुमानों में इनका स्तर 8.5 प्रतिशत निर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान मूल्यों पर घटक लागत पर स०घ०उ० में वृद्धि त्वरित अनुमानों में 16.1 प्रतिशत आंकी गई है जबकि संशोधित अनुमानों द्वारा 12.2 प्रतिशत का वृद्धि स्तर अभिलेखबद्ध किया गया है।

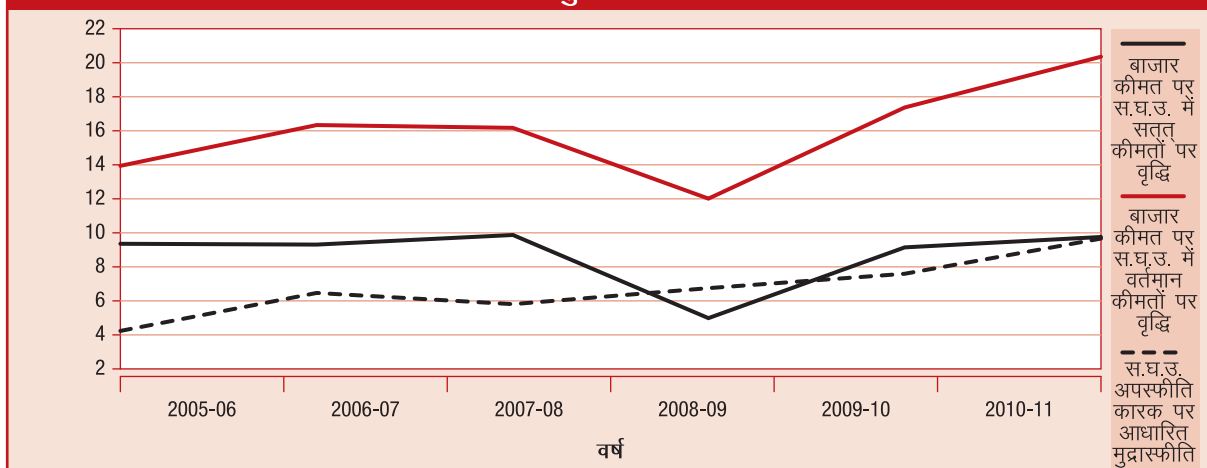
1.10 त्वरित अनुमान स०घ०उ० अपस्फीतिकारक तथा क्षेत्रक संघटन द्वारा यथामापित समग्र मुद्रास्फीति का विस्तार भी निर्दिष्ट करते हैं। कृषि तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में त्वरित अनुमान 2009-10 में वर्तमान मूल्यों के अर्थ में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई अनुमानित की गई है (स० अ० 2009-10 में 11.8 प्रतिशत की तुलना में) सतत् कीमतों के अर्थ में वृद्धि के 4.0 प्रतिशत होने से, अंतर्हित मुद्रास्फीति 16.8 प्रतिशत आंकी गई है। जहां तक उद्योग में वृद्धि दरों का संबंध है, संशोधन अपेक्षाकृत कम था तथा अंतर्हित मुद्रास्फीति वर्ष 2009-10 में 2.8 प्रतिशत आंकी गई है। वर्तमान तथा सतत् कीमतों की वृद्धि में संशोधनों के अनुसार सेवाओं में वर्ष 2009-10 में 7.6 प्रतिशत की अंतर्हित मुद्रास्फीति निर्दिष्ट हुई है (संशोधित अनुमानों के अनुसार 3.8 प्रतिशत)। अंतर्हित स०घ०उ० अपस्फीतिकारक द्वारा यथामापित मुद्रास्फीति के (स्तर बढ़ गए हैं जो प्रमुख वृहद् आर्थिक संकेतकों के अर्थ में वर्तमान तथा सतत् कीमतों के बीच वृद्धि में परिवर्तों के व्यापक होने में परिणामी हुए हैं (चित्र 1.1 तथा 1.2)

1.11 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने 7 फरवरी 2011 को वर्ष 2010-11 के लिए अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि हुई तथा अब यह ठोसाधारित है। वर्ष 2010-11 में वास्तविक स.घ.उ० में आंकी गई 8.6 प्रतिशत की वृद्धि, जो वर्ष 2009-10 में 8.0 प्रतिशत की संशोधित वृद्धि तथा वर्ष 2008-09 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद हुई थी, अर्थव्यवस्था पूर्व संकट स्तरों के सन्निकट पहुंच गई है। वर्ष 2010-11 में वृद्धि के अपघटन ने निर्दिष्ट किया कि यह कृषि में उछाल के अलावा उद्योग तथा सेवाओं में प्रमुख उप-क्षेत्रों में सापेक्षतया व्यापकाधारित थी। खाद्यान्नों में 6.5 प्रतिशत; तिलहनों में 11.9 प्रतिशत; कपास में 41.2 प्रतिशत; गन्ने में 15.2 प्रतिशत; फलों में 4.1 प्रतिशत; तथा सब्जियों में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर कृषि में सापेक्षतया तीव्रता से वृद्धि होने का अनुमान

चित्र 1.1 घटक लागत पर स.घ.उ. में वर्तमान तथा सतत् कीमतों पर वृद्धि तथा अपस्फीतिकारक पर आधारित मुद्रास्फीति



चित्र 1.2 बाजार कीमत पर स.घ.उ. में वर्तमान तथा सतत् कीमतों पर वृद्धि तथा अपस्फीतिकारक पर आधारित मुद्रास्फीति



है। इससे खाद्य कीमत की स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी यदि मांग में अपेक्षाकृत तीव्र दरों पर वृद्धि नहीं होती। उद्योग में वृद्धि राष्ट्रीय लेखों के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अर्थ में वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में तीव्र थी। वर्तमान राजकोषीय वर्ष में दूरसंचार सेवाओं, नागर विमानन तथा वित्तीय सेवाओं में प्रमुख संकेतकों के अर्थ में सशक्त निष्पादन तथा समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं को छोड़कर सेवाओं के स्तर में वृद्धि अगले वर्ष के लिए अपेक्षाकृत उज्ज्वल संभावनाएं निर्दिष्ट करती है। विनिर्माण क्षेत्र के अनुमानतः विगत वर्ष के समतुल्य स्तरों पर ही बने रहने तथा संरचना क्षेत्र में तेजी द्वारा अन्य उपक्षेत्रक संघटकों में हास के प्रतिसंतुलित होने के अनुमान से, उद्योग में वृद्धि के कमाधिक पिछले वर्ष हासिल 8 प्रतिशत के समस्तरो पर ही बने रहने का अनुमान है। मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वर्षानुवर्ष वृद्धि में हास का कुछ अंश विशाल मूल प्रभाव के कारण है, किन्तु

तिमाही-दर-तिमाही क्रमिक अनावर्तक सूचकांक उतार चढ़ाव भी एक धनात्मक किन्तु कमजोर संवेग प्रतिबिम्बित करते हैं जिसका करीबी अनुशीलन किया जाना आवश्यक है।

त्रैमासिक प्रवृत्ति

1.12 31 जनवरी 2011 को जारी त्वरित अनुमानों तथा मई 2010 में निर्गत 2009-10 के संशोधित अनुमानों के बीच वार्षिक स.घ.उ. अनुमानों में संशोधन स्तर वर्तमान तथा विगत वर्षों के लिए त्रैमासिक स.घ.उ. अनुमानों में कुछ संभावित संशोधन निर्दिष्ट करते हैं। त्रैमासिक स.घ.उ. में ये संशोधन किसी परवर्ती तिथि को उपलब्ध किए जाने की संभावना है। उपलब्ध आंकड़ों ने (मध्यवर्षीय विश्लेषण 2010 में भी सूचित) ने प्रथम दो तिमाहियों में से प्रत्येक में तथा साथ ही वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में 8.9 प्रतिशत पर वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि संवृद्धि संवेग निर्दिष्ट किया। वास्तविक स.घ.उ. में तथा इसके व्यापकाधारित

स्वरूप ने निर्दिष्ट किया कि वर्ष 2009-10 में आरम्भ हुए आर्थिक सुधार में संवेग आ गया है तथा यह वैश्विक संकट से पूर्व हासिल सशक्त स्तर पर है। सतत् बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में 10.4 प्रतिशत आंकी गई है। सुधार का मुख्य कारण राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों को माना गया है जैसाकि मांग पक्ष के संकलित आंकड़े प्रमाणित करते हैं। ऐसा मध्यावधि विश्लेषण 2010 में विस्तार में सूचित किया गया था।

सकल मांग तथा इसका संघटन

निजी खपत तथा निवेश में बढ़ोतरी ने मांग को पुनः वर्धित किया

1.13 स.घ.उ. (सतत् बाजार कीमतों पर) के व्यय अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के प्रभाव के आयामों का प्रकटन करते हैं। यद्यपि संकट वर्ष 2008-09 के द्वितीयार्ध में ही गहराया था, मांग पक्ष स.घ.उ. में त्रैमासिक आधार पर आपूर्ति पक्ष स.घ.उ. (घटक लागत पर सतत् मूल्य) में वृद्धि की तुलना में कहीं निम्नतर स्तरों पर वृद्धि हुई तथा वर्षानुवर्ष आधार पर इसे 2007-08 के स्तरों से आधे पर आंका गया था। वर्ष 2009-10 के लिए त्वरित अनुमानों द्वारा प्रभावी स.घ.उ. आंकड़ों के संशोधनों के कारण आर्थिक समीक्षा के पूर्ववर्ती संस्करणों में अभिलेखबद्ध संकट के प्रभाव के आयामों तथा अनुवर्ती सुधार में परिवर्तन सन्निहित था। निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि में ह्रास पहले सूचित किए गए वृद्धि ह्रास से निम्नतर था; राजकोषीय प्रेरण वर्ष 2008-09 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में 10.7 की वृद्धि के साथ (2008-09 के त्वरित अनुमानों के 16.7 प्रतिशत के स्तरों की तुलना में) केवल सामान्य ही था। राजकोषीय प्रेरण उपायों का वास्तविक प्रभाव वर्ष 2009-10 में ही परिलक्षित हुआ जब सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि 16.4 प्रतिशत आंकी गई थी। सकल पूंजी निर्माण के 2008-09 में तेजी से गिरने और 2009-10 के समान तेजी से

सुधरने का अनुमान है जिसका मुख्य कारण स्टॉकों में परिवर्तनों पर आरोप्य है। निर्यात वृद्धि में भी वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में अधोमुखी संशोधन हुआ। आयातों में भी केवल 1.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट होने का अनुमान लगाया गया जबकि अग्रिम अनुमानों में निर्दिष्ट यह प्रतिशतता 17.2 है।

1.14 सतत् बाजार कीमतों पर यथामापित मांग पक्ष स.घ.उ. में वर्ष 2010-11 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी 1.2); वर्तमान बाजार कीमतों के अर्थ में (सांकेतिक स.घ.उ.) इसे 20.3 प्रतिशत पर आंका गया है। सतत् बाजार कीमतों पर, यद्यपि कुल खपत व्यय तथा पूंजी निर्माण में 2010-11 में वर्षानुवर्ष ह्रास होने का अनुमान है, सरकार के निजी अंतिम उपभोग व्यय में तेजी आने; मूल प्रभाव के कारण तेजी से ह्रास होने; तथा सकल नियत पूंजी निर्माण और निवल निर्यातों में तेजी आने से, धनात्मक संघटनात्मक अंतरण निर्दिष्ट हुए हैं। वर्ष 2010-11 के लिए मांग पक्ष अनुमानों में अंतर्हित स.घ.उ. अपस्फीतिकारक द्वारा मापित, मुद्रास्फीति 9.6 प्रतिशत है। सतत् तथा वर्तमान मूल्यों पर घटक लागत पर स.घ.उ. के वृद्धि स्तरों पर आधारित समरूप अनुमान 9.0 प्रतिशत आंके गए हैं।

1.15 प्रमुख मांग पक्ष के संकलित आंकड़ों की वृद्धि में हिस्सों तथा अंशदान के स्तर निर्दिष्ट करते हैं कि वर्ष 2008-09 में मांग की मंदी का कारण अधिकांशतः सकल पूंजी निर्माण तथा निवल निर्यातों पर आरोप्य है (सारणी 1.3)। वर्ष 2009-10 में मांग पक्ष स.घ.उ. में उछाल का कारण भी इन्हीं दो घटकों पर आरोप्य है तथा यह निजी अंतिम उपभोग व्यय से वृद्धि में अपचित अंशदान स्तरों के कारण था। निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि का अपघटन निर्दिष्ट करता है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से वाले खाद्य, पेय पदार्थों तथा तम्बाकू के उप-समूह में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10, दोनों में ही वृद्धि के अर्थ में तीव्र गिरावट आई; यह उप-समूह और इसके साथ ही फर्नीचर और

सारणी 1.2 : सतत् बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि						
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 ^{अ.अ.}	2009-10 ^{त्व.अ.}	2010-11 ^{अ.अ.}
1. कुल अंतिम उपभोग व्यय	8.6	7.6	9.3	8.2	8.7	7.3
1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय	8.5	8.3	9.3	7.7	7.3	8.2
1.2 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	8.9	3.7	9.5	10.7	16.4	2.6
2. सकल पूंजी निर्माण	16.3	15.3	17.2	-3.1	13.8	8.8
2.1 सकल नियत पूंजी निर्माण	16.2	13.8	16.2	1.5	7.3	8.4
2.2 स्टॉक में परिवर्तन	26.9	31.5	31.1	-48.6	90.8	7.1
2.3 मूल्यवान वस्तुएं	-1.4	13.7	2.8	26.9	54.2	19.5
3. निर्यात	25.8	20.0	5.9	14.4	-5.5	12.0
4. घटाए आयात	32.5	21.3	10.2	22.7	-1.8	6.3
5. कमी	33.6	35.5	124.8	-140.9	-133.6	-220.2
2004-05 बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि	9.3	9.3	9.8	4.9	9.1	9.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

सारणी 1.3 : 2004-05 बाजार कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद में मांग पक्ष की वृद्धि, वृद्धि अंशदान और सापेक्ष अंश (प्रतिशत)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बाजार मूल्यों पर स.घ.उ.		9.3	9.3	9.8	4.9	9.1
खपत (निजी)		8.5	8.3	9.3	7.7	7.3
खपत (सरकारी)		8.9	3.7	9.5	10.7	16.4
सकल नियत पूंजी निर्माण		16.2	13.8	16.2	1.5	7.3
स्टॉक में परिवर्तन		26.9	31.5	31.1	-48.6	90.8
निर्यात		25.8	20.0	5.9	14.4	-5.5
आयात		32.5	21.3	10.2	22.7	-1.8
संवृद्धि में योगदान						
खपत (निजी)		54.2	52.5	54.9	90.5	47.8
खपत (सरकारी)		10.4	4.4	10.0	22.3	19.6
सकल पूंजी निर्माण		57.3	50.4	67.2	-44.3	72.3
सकल नियत पूंजी निर्माण		49.9	45.5	52.4	10.4	26.2
निवल निर्यात		-18.6	-10.2	-13.6	-57.6	-8.0
सापेक्ष हिस्सा						
खपत (निजी)	59.1	58.7	58.2	57.9	59.4	58.5
खपत (सरकारी)	10.9	10.9	10.3	10.3	10.9	11.6
सकल पूंजी निर्माण	32.8	34.9	36.2	39.0	35.1	38.2
सकल नियत पूंजी निर्माण	28.7	30.5	31.8	33.6	32.5	32.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

टिप्पणी : इनका जोड़ 100 नहीं होता क्योंकि सारणी में केवल प्रमुख मदें ही शामिल की गई हैं।

फर्निशिंग ही दो उपसमूह थे जिनमें वर्षानुवर्ष वृद्धि के अर्थ में हास हुआ (सारणी 1.4)। वर्ष 2009-10 की आर्थिक समीक्षा में यह निर्दिष्ट किया गया था कि राजकोषीय उपायों को वापस लेने का

क्रमनिर्धारण निवेश में सुधार द्वारा मार्गदर्शित होगा तथा नवीनतम आंकड़े निर्दिष्ट करते हैं कि सकल नियत पूंजी निर्माण में आई तेजी पूर्व-संकट स्तरों के अर्थ में पूर्ण नहीं हुई है।

सारणी 1.4 : निजी अंतिम उपभोग - 2004-05 की कीमतों पर वार्षिक वृद्धि और हिस्सा

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 ^{अन.अ.}	2009-10 ^{त्व.अ.}
	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)					
खाद्य, पेय पदार्थ और तम्बाकू		6.3	3.4	6.4	3.1	0.5
कपड़े और जूते		19.7	23.3	5.0	5.6	5.2
सकल किराया, ईंधन और बिजली		3.8	3.8	4.7	4.3	5.9
फर्नीचर, फर्निशिंग आदि		15.1	17.1	16.1	12.9	13.5
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं		8.8	8.7	4.5	6.9	8.9
परिवहन और संचार		5.2	8.1	7.4	9.2	14.2
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं		11.0	8.4	9.8	11.9	6.4
प्रकीर्ण वस्तुएं और सेवाएं		20.2	21.2	28.6	20.2	15.9
जोड़ निजी उपभोग		8.4	8.5	9.1	7.6	7.4
	कुल का हिस्सा (प्रतिशत)					
खाद्य, पेय पदार्थ और तम्बाकू	40.0	39.2	37.4	36.4	34.9	32.6
कपड़े और जूते	6.6	7.3	8.3	8.0	7.9	7.7
सकल किराया, ईंधन और बिजली	13.8	13.2	12.7	12.2	11.8	11.6
फर्नीचर, फर्निशिंग आदि	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	4.6
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8
परिवहन और संचार	19.3	18.7	18.7	18.4	18.6	19.8
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2
प्रकीर्ण वस्तुएं और सेवाएं	8.9	9.9	11.1	13.0	14.6	15.7
जोड़ निजी उपभोग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

बचतें तथा निवेश

सरकारी क्षेत्र की बचतें तथा कारपोरेट निवेश मंदी तथा अनुवर्ती सुधार को स्पष्ट करते हैं।

1.16 वर्ष 2009-10 के लिए सीएसओ के त्वरित अनुमानों में सकल घरेलू बचतें वर्तमान बाजार कीमतों (बचत दर) पर स.घ.उ. के 33.7 प्रतिशत पर आकलित की गई है। वर्ष 2008-09 के लिए बचत दर को भी 32.5 प्रतिशत के स्तर से संशोधित करके 32.2 प्रतिशत किया गया था। निजी क्षेत्र की बचतों के कमाधिक स्थैतिक रहते, यह सरकारी क्षेत्र की (अनिवार्यतः सार्वजनिक उद्यम) ही बचतें थी जो वर्ष 2008-09 में 0.5 प्रतिशत के संशोधित स्तर से बढ़ कर वर्ष 2009-10 में 2.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई (सारणी 1.5)। निजी क्षेत्र की बचतें विगत छः वर्षों में 30.1 प्रतिशत से 31.9 प्रतिशत की सीमा के बीच ही रहीं हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक संकट का इन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

1.17 वर्तमान बाजार कीमतों (निवेश दर) पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल पूंजी निर्माण में वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई। इसने केन्द्र तथा राज्यों द्वारा शुरू की गई राजकोषीय सुदृढीकरण प्रक्रिया को प्रतिबिम्बित किया जिसने अर्थव्यवस्था के लिए उच्चतर निवेश दरों के रूप में उच्च लाभांश अर्जित करना तथा इस प्रकार उच्चतर स.घ.उ. संवृद्धि दर

हासिल करना अनुमत किया। निवेश दर वर्ष 2009-10 में 36.5 प्रतिशत आकलित की गई जो वर्ष 2008-09 में 34.5 प्रतिशत के संकट प्रभावित स्तरों से उच्चतर है। तथापि, वर्ष 2009-10 में सकल नियत पूंजी निर्माण में तेजी नहीं आई है। वर्ष 2008-09 में निवेश दर में गिरावट अधिकांशतः निजी क्षेत्र, विशेष रूप से कारपोरेट क्षेत्र की निवेश दर में गिरावट के कारण थी। वर्ष 2009-10 में त्वरित अनुमानों के अनुसार, कारपोरेट क्षेत्र के निवेशों में तेजी आई है, पारिवारिक क्षेत्रक निवेश, जो वर्ष 2008-09 में काफी अधिक बढ़ गया था, ने पथ परिवर्तित किया तथा यह वापस पूर्व संकट स्तरों पर पहुंच गया है। इस प्रकार 2008-09 में संकट का प्रभाव मुख्यतः स्टॉकों में परिवर्तन के स्तरों में भी अभिव्यक्त था जिसमें 2009-10 में सुधार आया। तथापि त्वरित अनुमानों के अनुसार, सकल नियत पूंजी निर्माण वर्ष 2009-10 में 30.8 प्रतिशत आकलित किया गया है जो वर्षानुवर्ष आधार पर हास निर्दिष्ट करता है।

बचत-निवेश अंतर कम हुआ, किन्तु यह अभी भी व्यापक है

1.18 बचत निवेश का समग्र अंतर जो इन अनुमानों में अंतर्हित था, वर्ष 2008-09 में 2.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 में 2.8 प्रतिशत था। क्षेत्रों के अर्थ में अंतर ने वर्ष 2008-09 में सरकारी क्षेत्र अधिशेष का बढ़कर (-) 9.0 प्रतिशत होना निर्दिष्ट किया जो बाद में वर्ष 2009-10 में कम होकर (-) 7.0 प्रतिशत हो गया।

सारणी 1.5 : स.घ.उ. की तुलना में बचतों और निवेश का अनुपात (चालू बाजार कीमतों पर प्रतिशत)						
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 ^{अन.अ.}	2009-10 ^{त्व.अ.}
सकल घरेलू बचतें	32.4	33.5	34.6	36.9	32.2	33.7
सरकारी क्षेत्र	2.3	2.4	3.6	5.0	0.5	2.1
निजी क्षेत्र	30.1	31.0	31.0	31.9	31.7	31.6
पारिवारिक क्षेत्र	23.6	23.5	23.2	22.5	23.8	23.5
वित्तीय बचत	10.1	11.9	11.3	11.7	10.8	11.8
भौतिक परिसंपत्तियों में बचत	13.4	11.7	11.9	10.8	13.1	11.7
निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	6.6	7.5	7.9	9.4	7.9	8.1
सकल पूंजी निर्माण (निवेश)	32.8	34.7	35.7	38.1	34.5	36.5
सरकारी क्षेत्र	7.4	7.9	8.3	8.9	9.5	9.2
निजी क्षेत्र	23.8	25.2	26.4	28.1	24.6	24.9
कारपोरेट क्षेत्र	10.3	13.6	14.5	17.3	11.5	13.2
पारिवारिक क्षेत्र	13.4	11.7	11.9	10.8	13.1	11.7
सकल नियत पूंजी निर्माण	28.7	30.3	31.3	32.9	32.0	30.8
स्टॉक	2.5	2.8	3.4	4.0	2.0	3.3
मूल्यवान वस्तुएं	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.7
बचत-निवेश अंतर						
सरकारी क्षेत्र	-5.1	-5.5	-4.7	-3.9	-9.0	-7.0
निजी क्षेत्र	6.3	5.8	4.6	3.8	7.1	6.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

टिप्पणी : भूल-चूक और त्रुटियों के लिए किए गए समायोजन के कारण जोड़ में अंतर हो सकता है।

यह स्थिति विस्तारकारी नीतियों को प्रतिबिम्बित करती है तथा अंशतः संघटक पक्ष पर निजी क्षेत्रक बचत-निवेश संतुलन में उर्ध्वमुखी अंतरण द्वारा निर्मित थी और वृहद आर्थिक पक्ष पर इसने विदेशी मांग की तुलना में सापेक्षतया सशक्त घरेलू मांग को प्रतिबिम्बित किया। हालांकि निवेश में गिरावट से प्रत्युत्पन्न मांग स्तर में मंदी को देखते हुए विस्तारकारी राजकोषीय स्थिति को उपयुक्त समझा गया, भविष्य में राजकोषीय समेकत की प्रक्रिया को गहन करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता जिसकी पुनः शुरुआत वर्ष 2010-11 के बजट में की गई थी।

1.19 सभी क्षेत्रों में निवेश की दरों ने संकट के प्रभाव तथा सुधार के भिन्न-भिन्न स्तर निर्दिष्ट किए। कृषि क्षेत्र में संशोधनों के बाद भी निवेश वृद्धि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में सशक्त थी किन्तु वर्ष 2009-10 (त्वरित अनुमान) में यह 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मंद हो गई प्रतीत होती है (सारणी 1.6)। वानिकी तथा लॉगिंग में गिरावट जारी है। गिरावट की यह प्रक्रिया 2007-08 में प्रारम्भ हुई थी किन्तु 2009-10 में इसमें अत्यधिक तेज़ी आनी शुरू हुई।

मात्स्यिकी में क्षेत्रक निवेश सापेक्षतया स्थैतिक था। खनन तथा उत्खनन एवं संरचना के दो क्षेत्रों में निवेश में वर्ष 2009-10 में अत्यंत तीव्र तेज़ी आई। निम्न क्षेत्रों ने वर्ष 2009-10 में हासकारी रूझान दर्शाया:- बिजली, गैस तथा जलापूर्ति; रेलवे तथा संचार। व्यापार, होटलों तथा रेस्तरां में व्यापार के तीव्रता से हासित होने से निवेश की दरों में गिरावट आई; तीसरे वर्ष के लिए बैंकिंग तथा बीमा में गिरावट आई तथा स्थावर संपदा क्षेत्र मूल प्रभाव के कारण हासित हुआ।

उत्पादन और आपूर्ति

कृषि वृहद् आर्थिक स्थायित्व तथा स्थायी संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है

1.20 कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों में संवृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। यह पुनरस्मरणीय है कि इस क्षेत्र में 2007-08 को समाप्त हुए त्रयवर्ष में औसत

सारणी 1.6 : 2004-05 की कीमतों पर क्षेत्रक निवेश वृद्धि दरें

	सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी	13.8	4.7	15.8	22.5	3.7
कृषि	13.9	4.2	17.0	23.9	3.4
वानिकी और लॉगिंग	30.8	13.4	-20.2	-4.0	-13.5
मात्स्यिकी	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5
खनन और उत्खनन	40.0	15.6	13.3	-13.4	62.1
विनिर्माण	17.6	16.6	29.5	-31.6	34.8
पंजीकृत	39.3	11.0	37.3	-27.0	25.2
अपंजीकृत	-36.7	47.4	-2.6	-58.8	134.1
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	21.3	18.1	11.4	12.3	3.5
निर्माण कार्य	5.7	66.3	20.4	-24.7	16.8
व्यापार, होटल और रेस्तरां	26.7	40.3	-17.7	29.9	-27.4
व्यापार	22.6	44.9	-22.8	35.8	-32.7
होटल और रेस्तरां	49.2	19.5	10.4	7.0	-1.0
परिवहन, भंडारण और संचार	20.1	-7.4	25.9	37.6	0.9
रेलवे	14.6	12.9	13.7	22.5	9.3
अन्य साधनों द्वारा परिवहन	12.8	-14.8	29.6	12.8	-8.9
भंडारण	-285.7	14.9	7.1	62.4	-1.5
संचार	33.2	-7.8	30.1	86.7	6.6
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	6.2	-0.4	10.6	41.0	-3.3
बैंकिंग और बीमा	70.4	61.8	-6.8	-5.0	-26.1
स्थावर संपदा, आवासों का स्वामित्व, और व्यावसायिक सेवाएं	4.3	-3.3	12.0	44.0	-2.3
सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	19.6	12.3	18.4	-3.6	12.3
लोक प्रशासन और रक्षा	17.3	14.0	13.4	3.3	11.1
अन्य सेवाएं	22.7	10.2	25.0	-11.9	14.0
जोड़	17.0	15.3	17.7	-3.9	12.2

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

वार्षिक आधार पर 5.0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी जब वास्तविक स.घ.उ. में वृद्धि 9 प्रतिशत से अधिक थी। यह क्षेत्र 2010-11 की पहली छमाही में वास्तविक स.घ.उ. के 12.7 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। 1972 के बाद से सर्वाधिक कम दक्षिण-पश्चिमी मानसून पाने और 2009-10 में खरीफ़ खाद्यान्न उत्पादन के स्तरों में महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद, कृषि में मुख्यतया अच्छी रबी फसल के कारण 0.4 प्रतिशत का सीमान्तिक सुधार हुआ। रबी की फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पहले ही किए गए अनेक उपायों का वांछनीय प्रभाव हुआ। खेती का क्षेत्र भी पहले ऋणों को माफ़ करने और किए गए अन्य उपायों से और फिर अधिक लाभकारी मूल्य समर्थन द्वारा व्यापक रूप से समर्थित हुआ। सामान्य से अधिक वर्षा होने से, मौजूदा वर्ष में इस क्षेत्र की संवृद्धि की संभावनाएं उज्ज्वल थी, संवृद्धि 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 1.0 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 की पहली छमाही के दौरान 3.8 प्रतिशत हो गई। के. सां.सं. के अग्रिम अनुमानों में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों की संवृद्धि को 5.4 प्रतिशत पर रखा गया, जिसका निहितार्थ वर्ष 2010-11 में वास्तविक स.घ.उ. में 14.2 प्रतिशत के समग्र हिस्से से है। मौजूदा राजकोषीय वर्ष में संवृद्धि के स्तर के साथ भी, पूर्ण 11वीं योजना अवधि के 4 प्रतिशत प्रति वर्ष का लक्ष्य भी हासिल नहीं हो पाएगा।

1.21 2005-06 से 2008-09 तक के चार लगातार वर्षों में, खाद्यान्न उत्पादन ने एक उत्थानशील प्रवृत्ति दर्ज की और 2008-09 में यह 234.47 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। 2009-10 के दौरान (चौथा अग्रिम अनुमान) 2009 में देश के विभिन्न भागों में सूखे के लंबे दौरों के कारण खाद्यान्न उत्पादन गिरकर 218.20 मिलियन टन रह गया। लगभग सभी फसलों की उत्पादकता पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे 2009 में उनका उत्पादन कम हो गया। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार (जिसमें केवल खरीफ़ फसलें शामिल हैं), 2010-11 के दौरान खरीफ़ खाद्यान्नों का 114.63 मिलियन टन का उत्पादन अनुमानित है जो 125.31 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है किन्तु 2009-10 (चौथा अग्रिम अनुमान) के दौरान रिकार्ड किए गए 103.84 मिलियन टन के खरीफ़ खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। 2010-11 में लक्ष्य की तुलना में अनुमानित खरीफ़ खाद्यान्न उत्पादन में कमी का मुख्य कारण देश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में सूचित की गई सूखे की स्थिति है।

1.22 देश ने साठ के दशक के मध्य वर्षों से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में अच्छी प्रगति प्राप्त की है। आज, दूध, गेहूँ, चावल, फलों और सब्जियों जैसी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान काफी ऊपर है। तथापि, खाद्य मदों की बढ़ती हुई मांग और कई वस्तुओं में सापेक्षतया धीमी आपूर्ति अनुक्रिया के होने से भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति प्रतिकूल है, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति अक्सर बढ़ जाती है। साठ के दशक में हासिल प्रौद्योगिकीय प्रगति धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। एक दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता को पहले से भी कहीं अधिक महसूस किया

जा रहा है। लगभग 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की लक्षित संवृद्धि को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में दीर्घ संवृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु कृषि क्षेत्र में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के द्वारा, निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। कृषि उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि उत्पादन को प्रोत्साहित करने में अंशतः सहायता करेगी; फिर भी विवादास्पद विषय यह है कि वर्धित उत्पादन का कितना भाग उत्पादक को उपचित होगा और कितना भाग बिचौलियों द्वारा संविभाजित किया जाएगा। देश भर में खाद्य मदों में खेतों से सीधे खाने तक की और आपूर्ति कड़ियों का सृजन उच्चतर उत्पादक कीमतों के साथ किसानों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण होगा और साथ ही इसमें अंतिम-उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होंगी।

कीमतों और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है।

1.23 मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। वर्षानुवर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में दिसंबर 2009 में आरंभ वृद्धि का रुझान मौजूदा राजकोषीय वर्ष में भी जारी रहा। वित्त वर्ष 2010-11 अप्रैल 2010 में 11.0 प्रतिशत की द्विअंकीय शीर्षस्थ मुद्रास्फीति के साथ शुरू हुआ। अप्रैल-जुलाई 2010 में द्विअंकीय रहने के पश्चात्, शीर्ष मुद्रास्फीति घटकर एकल अंकों में आई और अगस्त 2010 में यह 8.8 प्रतिशत थी। नवंबर 2010 में शीर्षस्थ मुद्रास्फीति 7.5 प्रतिशत थी; किंतु यह प्रवृत्ति प्रतिवर्तित हो गई और दिसंबर 2010 में मुद्रास्फीति 8.4 प्रतिशत थी। इस वर्ष अच्छा मानसून होने के बावजूद, वर्धित स्तरों पर शीर्ष मुद्रास्फीति का कारण खाद्य मुद्रास्फीति के उच्च स्तर थे। खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति जो नवंबर, 2010 में घटकर एकल अंकीय रह गई थी, पुनः उछलकर द्वि अंकीय हो गई और दिसंबर 2010 में यह 13.6 प्रतिशत थी।

1.24 दिसंबर 2010 में मुद्रास्फीति में उछाल का श्रेय विशेषकर सब्जियों, प्याज, टमाटर, फलों, दूध, अंडों और मछली में आपूर्ति अवरोधों को जाता है। दिसंबर 2010 के दौरान प्याज की कीमतों में अचानक उछाल, प्याज की फसल को क्षति पहुंचने के कारण परिलक्षित हुआ। यह उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य कीमत मुद्रास्फीति मुख्यतया खराब मानसून के कारण दालों, अनाजों और चीनी में अधिक मुद्रास्फीति द्वारा चालित थी। अर्थव्यवस्था की तीव्र संवृद्धि के कारण क्रय शक्ति में वृद्धि और एमएनआरईजीए जैसे समावेशी कार्यक्रमों ने मुद्रास्फीति की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति में अंशता योगदान दिया। प्राथमिक वस्तुओं में औसत मुद्रास्फीति अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 10 प्रतिशत की तुलना में औसतन 18 प्रतिशत सूचित की गई। घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार मुद्रास्फीति पर मांग पक्ष दबाव में परिणामी हुआ। वैश्विक सुधार के चलते घरेलू मांग और उच्चतर वैश्विक वस्तु कीमतों दोनों से मुद्रास्फीतिकारी दबाव बना हुआ है।

1.25 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य का भार थोक मूल्य सूचकांक में भार की तुलना में अधिक है। समग्र सीपीआई (आईडब्ल्यू) मुद्रास्फीति, वर्षानुवर्ष नवंबर 2008 से डब्ल्यूपीआई से अधिक बनी रही; यह मौजूदा राजकोषीय वर्ष में भी अधिक बनी हुई है। अगस्त 2010 में, सभी कीमत सूचकांकों के संदर्भ में मुद्रास्फीति, 15 लगातार महीनों तक द्वि-अंकीय बने रहने के पश्चात् एकल अंक पर आ गई थी। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति दिसंबर 2009 में 14.97 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2010 में 9.47 प्रतिशत थी। वर्षानुवर्ष आधार पर, कृषि कामगारों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण कामगारों (सीपीआई-आरएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में मुद्रास्फीति दिसंबर 2009 में क्रमशः 17.21 और 16.99 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2010 में क्रमशः 7.99 प्रतिशत और 8.01 प्रतिशत रही।

1.26 वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के निर्माण के संदर्भ में, अर्थात् मार्च 2010 के स्तरों की तुलना में दिसंबर 2010 में डब्ल्यूपीआई सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.9 प्रतिशत की तुलना में 6.11 प्रतिशत का स्तर निर्दिष्ट किया। मूल प्रभाव और मूल्य प्रभाव के अर्थ में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति का विघटन 2010-11 में मुद्रास्फीति के स्तरों में वृद्धि का विशाल आधार प्रभाव दर्शाता है; हालांकि हाल ही के महीनों में इसमें एक संतुलनकारी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। यह प्राथमिक वस्तुओं में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति के विघटन के बारे में भी सही है।

1.27 अतः क्रमिक माह-दर-माह आधार पर मुद्रास्फीति में उभरती हुई प्रवृत्ति को मॉनीटर करना अनुदेशात्मक है। चूंकि ऐसे उपाय के साथ आवधिकता जुड़ी हुई है, आंकड़ों का सामान्यीकरण करने से इस दिशा में हुए परिवर्तनों, यदि कोई हैं, और उसमें अंतःस्थापित संवेग के संकेत मिलेंगे। शीर्ष मुद्रास्फीति का आवर्ती रूप से समायोजित क्रमिक माप सितंबर, 2010 में उछाल निर्दिष्ट करता है, जिसके बाद अगले दो माहों में संतुलन की स्थिति रही; दिसंबर 2010 में पुनः विशाल वृद्धि हुई, जो अत्यधिक उच्च संवेग को निर्दिष्ट करती है (चित्र 1.3)। मौजूदा राजकोषीय वर्ष में मूल

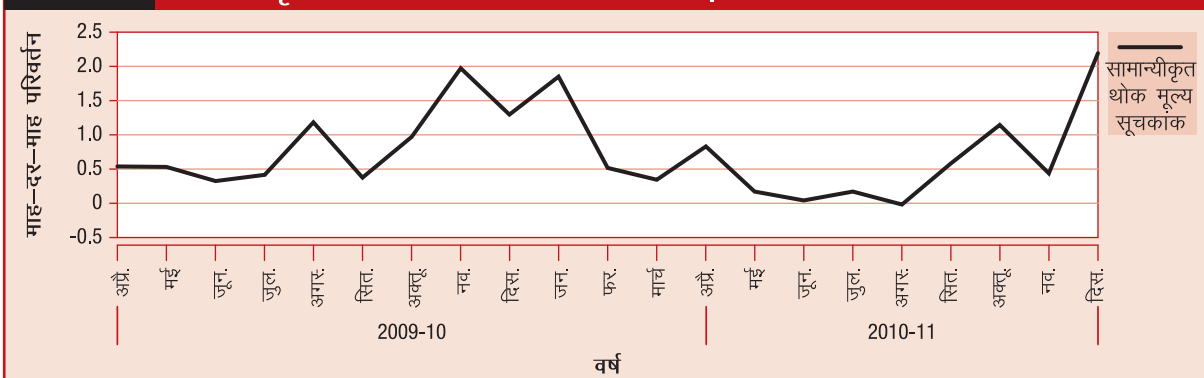
मुद्रास्फीति भी बढ़ी जो यह संकेत देती है कि खाद्य मदों में मुद्रास्फीति एक अधिक सामान्यीकृत संवृत्ति में आगे अंतरित हो गई होगी। डब्ल्यूपीआई में 65 प्रतिशत के भारांश के साथ विनिर्मित मदों में मुद्रास्फीति जनवरी 2010 से 4 प्रतिशत के स्तर से ऊपर रही है और अप्रैल 2010 में 6.4 प्रतिशत पर पहुंचने के पश्चात् इसने एक संतुलित प्रवृत्ति प्रदर्शित की। मध्यवर्तियों में मुद्रास्फीति के स्तरों और मजदूरी वस्तुओं में वृद्धि के औद्योगिक उत्पादन हेतु निहितार्थ हैं।

उद्योग और अवसंरचना

हालिया आंकड़े उतार-चढ़ाव और घटते संवेग को निर्दिष्ट करते हैं।

1.28 आईआईपी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में संवृद्धि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान उत्प्लावक थी। विनिर्माण क्षेत्र ने, विशेषरूप से, विलक्षण मजबूती प्रदर्शित की और इन दो तिमाहियों के दौरान इसमें क्रमशः 12.6 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई। मासिक आधार पर आईआईपी आंकड़े निर्दिष्ट करते हैं कि आईआईपी में संवृद्धि नवम्बर, 2009 में 11.3 प्रतिशत से तीव्र रूप से गिरकर नवम्बर, 2010 में 2.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर), के लिए आईआईपी में संवृद्धि पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि में हासिल 7.4 प्रतिशत की संवृद्धि के स्तर की तुलना में 9.5 प्रतिशत आकलित की गई है। आईआईपी संबंधित आंकड़ों ने मौजूदा राजकोषीय वर्ष में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए हैं, इसमें संवृद्धि 2.7 प्रतिशत से 16.6 प्रतिशत की सीमा में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न रही। जबकि पहले इस उतार-चढ़ाव को प्रयोग आधारित वर्गीकरण में पूंजी वस्तुओं के साथ जोड़ा गया था, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं और आधारभूत वस्तुओं जैसे संघटक नवम्बर, 2010 में हास के मुख्य अवसादक रहे। सीएसओ ने 11 फरवरी, 2011 को दिसंबर, 2010 के माह के लिए आईआईपी आंकड़े जारी किए हैं। वर्षानुवर्ष आईआईपी में दिसम्बर, 2010 में 1.6 प्रतिशत की और अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 1.3 सामान्यीकृत क्रमिक माह-दर-माह घट-बढ़



12 आर्थिक समीक्षा 2010-11

1.29 आईआईपी के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में विनिर्माण वृद्धि दर गिरकर 9.7 प्रतिशत रह गयी। पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान हासिल 16.8 प्रतिशत की चरम संवृद्धि की तुलना में, यह संवृद्धि दर संतुलित थी। विनिर्माण क्षेत्र में ही, पूंजी वस्तु खंड संवृद्धि का मुख्य चालक रहा; इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया, वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में इसने 3.5 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की, पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान इसमें उछाल होकर यह वृद्धि 45.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी और तब से यह द्विअंकीय ही बनी हुई है।

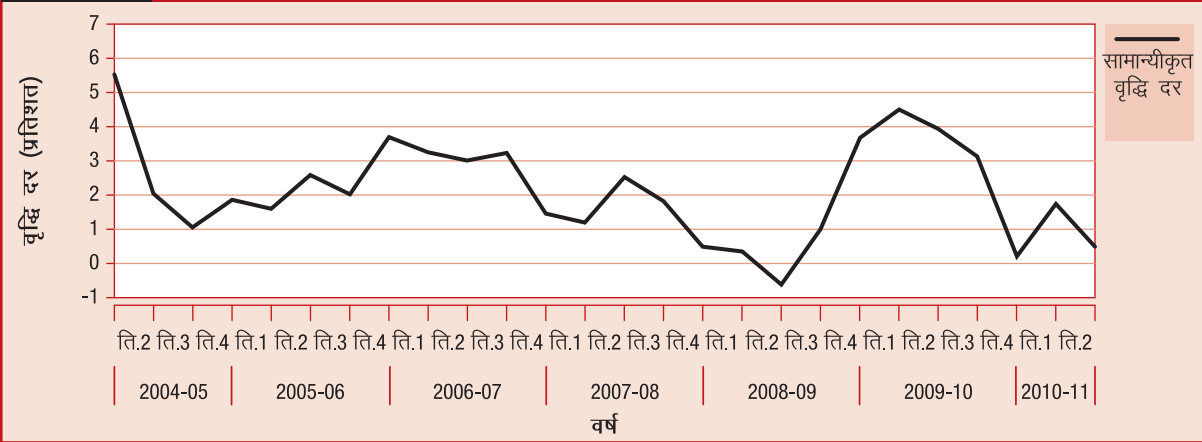
1.30 सुधार के पश्चात् औद्योगिक उत्पादन संवृद्धि अधिकांशतः कुछेक क्षेत्रों द्वारा चालित है यथा कपास, वस्त्र, चमड़ा, खाद्य उत्पादों और धातु उत्पादों में पुनरुद्धार के साथ-साथ आटोमोटिव क्षेत्र। कुछ क्षेत्रों ने अत्यधिक माह-दर-माह उत्पादन उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए हैं। घरेलू-मांग चालित औद्योगिक क्षेत्र पर अनुकूल मानसूनों का प्रभाव व्यापक नहीं रहा है। विशेषकर, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ खंड में इसके प्रभाव, जो यद्यपि अभी तक ज्ञात नहीं

है, का इस राजकोषीय वर्ष की चौथी तिमाही में मूर्त होने की आशा है। तथापि, एक उच्चतर आधार प्रभाव दिसम्बर, 2010 और जनवरी 2011 के महीनों में औद्योगिक संवृद्धि दर को प्रभावित कर सकता है और तदनुसार यह मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए स.घ.उ. में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान को संतुलित कर सकता है। चूंकि इसमें एक विशाल आधार प्रभाव संलिप्त है, तिमाही-दर-तिमाही सामान्यीकृत क्रमिक संवृद्धि संवेग और दिशा द्वारा निर्दिष्ट प्रवृत्ति को अवलोकित करना उपयोगी होगा। तिमाही-दर-तिमाही सामान्यीकृत शीर्ष आईआईपी ने अधिकांशतः पूंजी वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं में घट-बढ़ के चलते काफी उत्प्लावकता निर्दिष्ट की है। (चित्र 1.4)। आईआईपी मंदी का अल्पकालिक स्वरूप यह बताता है कि इस मंदी का स्वरूप किसी स्थायी समस्या के संकेत के बजाय छोटे मोटे धक्कों का ही है।

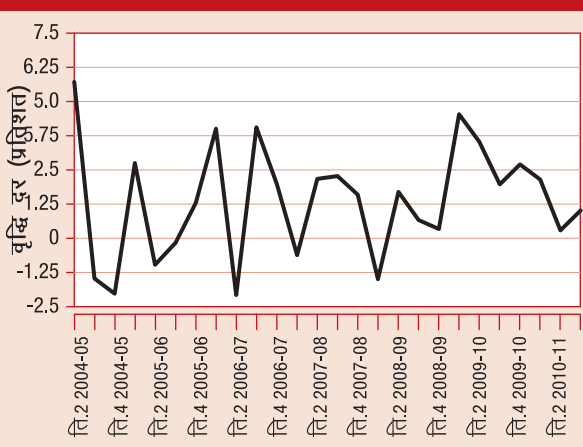
छह मूल उद्योग बढ़ रहे हैं; किन्तु पूर्ण उत्साह से नहीं

1.31 छह मूल उद्योगों, जिनका अवसंरचना पर काफी अधिक प्रभाव है और जिनकी आईआईपी में 26.7 प्रतिशत की संयुक्त

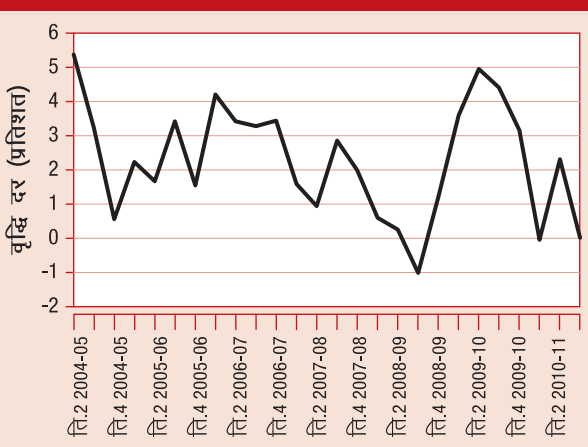
चित्र 1.4 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा इसके संघटकों में क्रमिक (सामान्यीकृत) वृद्धि दर (%)

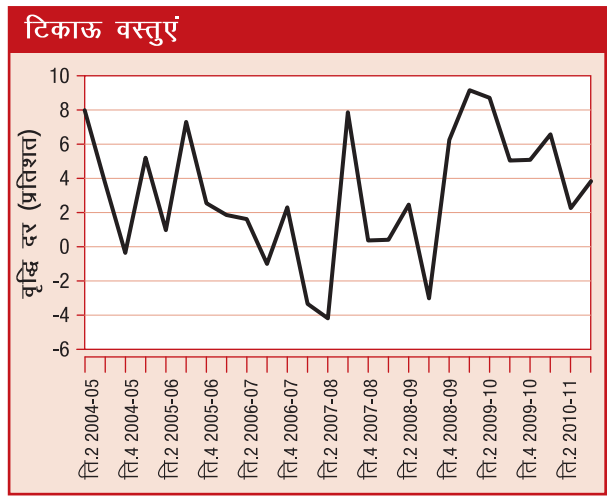
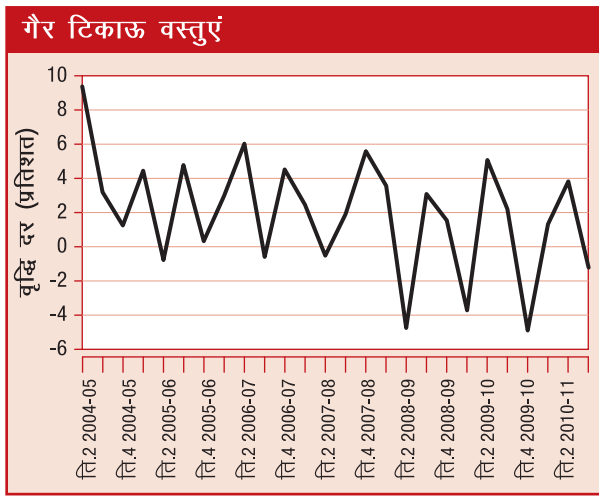
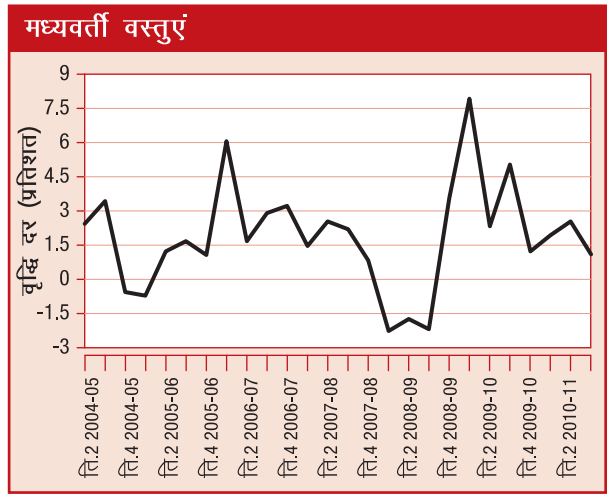
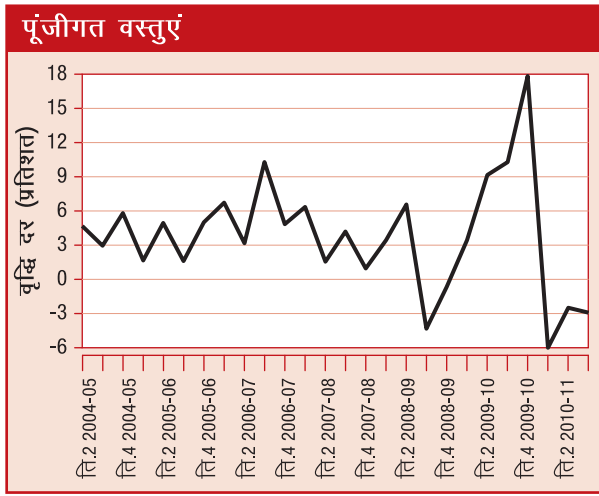
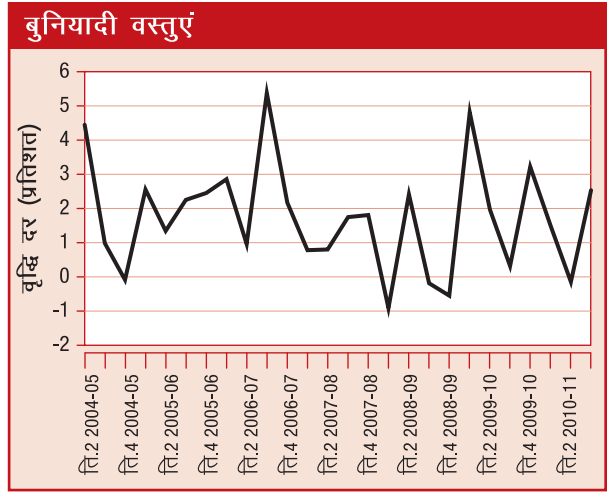
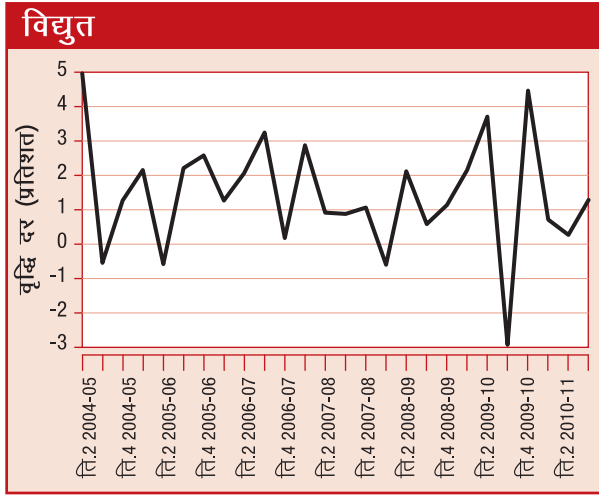


खनन



विनिर्माण





भारता है, के दिसम्बर, 2009 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2010 में 6.6 प्रतिशत (अनंतिम) की संवृद्धि दर्ज की। अप्रैल-दिसम्बर, 2010-11 के दौरान, इन मूल उद्योगों ने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 4.7 प्रतिशत की तुलना में 5.3 प्रतिशत (अनंतिम) की संवृद्धि दर्ज की।

1.32 2010-11 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिजली उत्पादन का लक्ष्य 7.7 प्रतिशत बढ़कर 830.757 बिलियन केडब्ल्यूएच पर पहुंचने का था। विद्युत उत्पादन में संवृद्धि अप्रैल-दिसम्बर, 2009 के दौरान लगभग 6.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान लगभग 4.5 प्रतिशत थी। अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के

दौरान, नाभिकीय, जल-विद्युत और तापीय विद्युत यूनिटों द्वारा उत्पादन में क्रमशः 33 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का समग्र संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान प्राप्त किए गए पीएलएफ से कम होते हुए भी, मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए 71.35 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया। अप्रैल-दिसंबर, 2010 के दौरान, शीर्ष और कुल ऊर्जा घाटे पिछले वर्ष की सदृश अवधि के दौरान 12.6 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत से गिरकर क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत रह गए, जिसका कारण मुख्यतया विद्युत की आवश्यकता में वृद्धि की तुलना में उसकी उपलब्धता में वृद्धि का अधिक होना था।

1.33 मौजूदा वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 37.96 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) होना अनुमानित है, जो 2009-10 के दौरान 33.69 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के उत्पादन से लगभग 12.67 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010-11 में प्राकृतिक गैस, जिसमें कोयला बेड मिथेन भी शामिल है, का अनुमानित उत्पादन 53.59 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है जो 2009-10 में 47.51 बीसीएम के उत्पादन से 12.80 प्रतिशत अधिक है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में वृद्धि मुख्यतया केजी डीपवाटर ब्लॉक के कारण है। कच्चे कोयले का उत्पादन अप्रैल से नवम्बर, 2010 के दौरान पिछले वर्ष की सदृश अवधि में 317.79 मिलियन टन की तुलना में 319.80 मिलियन टन था। इसी अवधि में कोकिंग कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 25.64 एमटी की तुलना में 28.72 एमटी था, जो 12.01 प्रतिशत की संवृद्धि दर्शाता है।

1.34 अप्रैल-नवम्बर, 2010 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर माल ढुलाई अप्रैल-नवम्बर, 2009 में 574.40 मिलियन टन की तुलना में 593.93 मिलियन टन थी - जो 3.31 प्रतिशत की वृद्धि है। यह 605.11 मिलियन टन के समानुपातिक लक्ष्य से 11.68 मिलियन टन कम था। संवृद्धि में यह कमी मुख्यतया लौह अयस्क में ऋणात्मक संवृद्धि के चलते थी। मौजूदा वर्ष में लौह अयस्क लदान मुख्यतया उड़ीसा और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रभावित हुआ है। नक्सलवादियों द्वारा प्रायिक बंधों ने विशेष रूप से पूर्व तटीय रेलवे के बैलादिला क्षेत्र में ढुलाई को प्रतिकूलतः प्रभावित किया।

अवसंरचना-मिला जुला निष्पादन

1.35 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा एकल लेन/मध्यवर्ती लेन वाला है; लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा दो लेन के स्तर का है और शेष 23 प्रतिशत हिस्सा चार लेन स्तर अथवा उससे अधिक का है। वर्ष 2010-11 में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के विभिन्न चरणों के अंतर्गत नवम्बर, 2010 तक की कुल उपलब्धि लगभग 1007 कि.

मी. रही है। 2010-11 के दौरान, एनएचडीपी के अंतर्गत, नवम्बर, 2010 तक लगभग 3780 कि. मी. की कुल लम्बाई की परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

1.36 नागर विमानन क्षेत्र में, अनुसूचित अंतर्देशीय यात्री यातायात जनवरी-दिसम्बर, 2010 के दौरान 2009 की सदृश अवधि में 43.3 मिलियन के यातायात के स्तर की तुलना में 19 प्रतिशत की संवृद्धि दर के साथ बढ़कर 51.53 मिलियन हो गया। हवाई संवाहित अंतर्देशीय माल 30 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज करते हुए 2009 में 3.4 मिलियन टन से बढ़कर 2010 में 4.7 मिलियन टन हो गया। फिलहाल 12 अनुसूचित हवाई कंपनियां प्रचालनात्मक हैं (10 यात्री और 2 मालवहन हवाई कंपनियां)। उनके बेड़े में वायुयानों की कुल संख्या बढ़कर दिसम्बर, 2010 के अंत तक 419 हो गई है। दिसम्बर, 2010 में अननुसूचित प्रचालकों की कुल संख्या 121 हो गई थी, जिनके बेड़े में 360 हवाई जहाज थे।

1.37 निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भागीदारी के चलते, कुल टेलीफोन कनेक्शनों में निजी क्षेत्र का हिस्सा, 1999 में मात्र 5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर नवम्बर, 2010 में 84.5 प्रतिशत हो गया। टेलीघनत्व जो टेलीकॉम अंतर्वेशन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, मार्च 2004 में 7.02 प्रतिशत से बढ़कर नवम्बर, 2010 में 64.34 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण टेलीघनत्व जो मार्च 2004 में 1.57 प्रतिशत से अधिक था, नवम्बर, 2010 के अंत तक बढ़कर 30.18 प्रतिशत हो गया। शहरी टेलीघनत्व, मार्च 2004 में 20.74 प्रतिशत से बढ़कर नवम्बर, 2010 के अंत में 143.95 प्रतिशत हो गया।

1.38 150 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली केन्द्रीय-क्षेत्रक परियोजनाओं में लगने वाले अधिक समय और अधिक लागत में सुस्थिर कमी देखी गयी है जिसका श्रेय संबद्ध मंत्रालयों द्वारा निकट अनुवीक्षण और प्रणालियों में सुधारों को जाता है। पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से अनुमोदित लागतों की तुलना में अधिक लागतों की जांच दर्शाती है कि ये अधिक लागतें मार्च 1991 में 61.6 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2008 में 12.06 प्रतिशत रह गईं। तथापि, मार्च 2008 से उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गई जब अधिक लागतें मार्च 2010 में 14.72 प्रतिशत पर पहुंच गईं और फिर और बढ़कर अक्टूबर, 2010 में 20.7 प्रतिशत हो गईं। यह वृद्धि अंशतः अनुवीक्षण प्रणाली में 150 करोड़ रुपए से कम की लागत वाली परियोजनाओं को शामिल न करने के कारण है क्योंकि इनके लागत अधिक्य अपेक्षाकृत बड़ी योजनाओं की तुलना में कम थे। यह बढ़त अंशतः 2006-07 में इस्पात और सीमेंट की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण भी है।

1.39 समग्र रूप से, अवसंरचना क्षेत्र में कार्य निष्पादन मिला जुला रहा है; कुछ क्षेत्रों ने जैसेकि दूरसंचार ने काफी अच्छा निष्पादन किया है और कुछ अन्यो में उपलब्धियां लक्षित से कम रही हैं। 2007-08 से 2009-10 के दौरान क्षमता वर्धन विद्युत,

सड़कों (एनएचडीपी), नई रेलवे लाइनों और रेलवे लाइनों को दोहरा करने में लक्ष्य, की तुलना में कम रहा। उप क्षेत्र जहां वास्तविक लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों से अधिक अथवा निकट रहे हैं, वे हैं- दूरसंचार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत किए गए गांव, रेलवे लाइन विद्युतीकरण, रेलवे गेज रूपांतरण और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत नई सड़कों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण। अवसंरचना में निवेश 2008-09 में स.घ.उ. के 7.18 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में बढ़कर 8.37 प्रतिशत होने की आशा है। अवसंरचना घाटे में तीव्र अपचयन एक वर्धनात्मक वैश्वीकृत आर्थिक माहौल में प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण है।

सेवा क्षेत्र-प्रत्याशित संवृद्धि चालक

1.40 सेवा क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में स.घ.उ. में 57.3 प्रतिशत हिस्से; 2009-10 में 10.1 प्रतिशत की संवृद्धि; अप्रैल 2000 से नवम्बर, 2010 के दौरान केवल वित्तीय और वित्तीय भिन्न सेवाएं श्रेणी द्वारा 21 प्रतिशत के उच्च हिस्से के योगदान के साथ एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों में उच्च हिस्सा; और 2010-11 की पहली छमाही में 27.4 प्रतिशत निर्यात संवृद्धि के साथ कुल निर्यातों में 35 प्रतिशत हिस्से के साथ, एक प्रबल भूमिका निभाई है। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स.घ.उ. में सेवा क्षेत्र के हिस्सों की तुलना दर्शाती है कि भारत के अधिकांश राज्यों में भी सेवा क्षेत्र एक प्रबल क्षेत्र है।

1.41 उच्च संवृद्धि वाली सेवा श्रेणियां हैं-वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यवसायिक सेवाएं; तथा परिवहन भंडारण और संचार, जिनमें परवर्ती श्रेणियां 2009-10 में 15 प्रतिशत की उच्च संवृद्धि के साथ पहली श्रेणियों से आगे रहीं। व्यापार, होटल तथा रेस्तरां में वृद्धि, जो 2008-09 में धीमी हो गई थी, में 2009-10 में संतुलित सुधार हुआ। उपश्रेणियों में वर्ष 2008-09 में संचार (25.7 प्रतिशत), लोक प्रशासन तथा रक्षा (22.1 प्रतिशत), बैंकिंग और बीमा (13.9 प्रतिशत) तथा भंडारण (11.6 प्रतिशत) द्वारा द्विअंकीय वृद्धि दर्ज की गई। ऋणात्मक वृद्धि केवल होटलों तथा रेस्तरां (-3.5 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई। व्यवसाय सेवाओं में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं कम्प्यूटर संबंधित सेवाएं; तथा अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, बाजार अनुसंधान, व्यवसाय तथा प्रबंधन परामर्श, संरचनात्मक इंजीनियरी और विज्ञापन जैसी कई सेवाओं को शामिल करने वाली श्रेणी जिनका स.घ.उ. में अंश क्रमशः 3.26 प्रतिशत तथा 0.88 प्रतिशत है। जबकि कम्प्यूटर संबंधित सेवाओं ने, जिनमें वर्ष 2008-09 में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वैश्विक संकट के कारण वर्ष 2009-10 में 5.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं ने वर्ष 2008-09 तथा 2009-10, दोनों में क्रमशः 19.6 प्रतिशत

तथा 19.9 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की। अन्य सेवाओं में, स.घ.उ. के सापेक्ष अंश के अर्थ में शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं; वर्ष 2009-10 में उनकी संवृद्धि दरें क्रमशः 13.9 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत थी। जबकि संरचना समाहित कुल सेवाओं में वृद्धि 9.7 प्रतिशत की थी, संरचना को छोड़कर कुल सेवाओं में वर्ष 2009-10 में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 (अ.अ.) में वे क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत की दर पर बढ़े सेवा क्षेत्र के लिए संभावनाएं जो अमरीका में सबप्राइम संकट तथा वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों के कारण मंद हो गई थीं, एक बार पुनः उज्ज्वल हो गई हैं। विभिन्न सेवाओं में विभिन्न सेवा फर्मों के हालिया व्यवसाय निष्पादन संकेतक भी इस स्वास्थ्यकर पूर्वानुमान को समर्थित करते हैं। संकट वर्ष के दौरान भी, वार्षिक सेवा वृद्धि 10 प्रतिशत के स्तर तक रही थी जिसका अनुक्षण इसने वर्ष 2005-06 से किया है। यह समग्र स.घ.उ. वृद्धि के विपरीत है जो वर्ष 2007-08 में 9.3 प्रतिशत से गिर कर वर्ष 2008-09 में 6.8 प्रतिशत रह गई थी।

वैदेशिक क्षेत्रक घटनाक्रम

वैश्विक अर्थव्यवस्था संवृद्धि संवेग के सहायतार्थ उत्थान पर

1.42 डब्ल्यूईओ के अपडेट (25 जनवरी 2011) के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2010 में 5.0 प्रतिशत की तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है; यह वृद्धि हालिया विगत की एक उच्चतम वृद्धि थी तथा पूर्व संकट अवधि में मजबूत स्तरों के अनुकूल समतुल्य है। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि सशक्त बनी रही हालांकि प्रगत देशों की संवृद्धि मंद है तथा वे विशाल राजकोषीय घाटे तथा उच्च सरकारी ऋण और बेरोजगारी के स्तरों के चलते अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। यह वर्तमान अंदाजे में वैश्विक संवृद्धि प्रक्रिया के द्विगति स्वरूप को निर्दिष्ट करता है। हालांकि वर्ष 2010 में संवृद्धि वर्ष 2009 में कमजोर स्तरों से आया अंशतः उछाल था, वर्ष 2011 तथा 2012 के लिए लगभग 4.5 प्रतिशत के अनुमान संभावनाओं को निर्दिष्ट करते हैं। आईएमएफ की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बाजार अपडेट (जनवरी 2011) में यह अवलोकन किया गया है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता अभी भी सुनिश्चित की जानी है तथा महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना अभी शेष है जो इस प्रकार हैं: अभी तक अपूर्ण तुलनपत्र पुनर्संरचना प्रक्रिया में धीमी प्रगति; यूरो क्षेत्र में बैंकिंग तथा सावरेन ऋण जोखिमों के बीच अन्योन्य क्रिया; तथा स्थिरता के संचालन हेतु वित्तीय क्षेत्र में अधिक विनियामक सुधारों की आवश्यकता। तथापि, अनेक उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आस्ति तथा ऋण बाजारों में बुलबुलों के संबद्ध जोखिम के साथ पूंजी अंतर्वाहों में उछाल आया है। सशक्त वैश्विक मांग की अनुक्रिया में आपूर्ति बाधाओं के साथ युग्मित बढ़ती मुद्रास्फीति के चिह्न भी दृष्टिगोचर हुए हैं।

व्यापार घटनाक्रम

आयात धीमें हो रहे हैं; निर्यातों में तेजी आ रही है तथा व्यापार घाटा कम होना निर्धारित है

1.43 वैश्विक व्यापार प्रमात्राओं के समनुरूप भारत के निर्यात 2008-09 के मध्यमार्ग में वैश्विक वित्तीय संकट के गहराने के पश्चात तेजी से गिरे; 2009-10 के द्वितीयार्ध में ये बढ़े और यह बढ़त 2010-11 में जून 2010 तक जारी रही। तत्पश्चात, अक्टूबर 2010 तक वृद्धि में ह्रास हुआ तथा तदनंतर तेजी दर्शाती हुई यह दिसम्बर 2010 में 36.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, यह वृद्धि विगत दो वर्षों में उच्चतम थी। फिर भी, अप्रैल-दिसम्बर 2010-11 में संचयी निर्यात वृद्धि 29.5 प्रतिशत थी तथा इस अवधि के दौरान संचयी निर्यात 164.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गए थे। वर्तमान संकेतक यह हैं कि भारत न केवल 200 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा बल्कि वर्ष 2010-11 में इसे पार कर जाएगा। भारत के पण्य वस्तु आयात भी वैश्विक मंदी से प्रभावित होकर वर्ष 2009-10 में (-) 5.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के साथ गिरकर 288.4 बिलियन के स्तर पर पहुंच गए। यह पीओएल आयातों की वृद्धि में 7.0 प्रतिशत की गिरावट तथा पीओएल भिन्न आयातों की वृद्धि में 4.2 प्रतिशत की गिरावट के कारण था। पीओएल आयात वृद्धि में कमी मुख्यतया भारतीय कच्चे तेल के आयात समूह में 7.7 प्रतिशत की प्रमात्रात्मक वृद्धि के बावजूद आयात कीमत में 16.5 प्रतिशत गिरावट के कारण थी।

1.44 व्यापार घाटा (सीमाशुल्क आधार पर) वर्ष 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.4 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 80.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 82 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2008-09 में व्यापार घाटा 118.4 बिलियन अमरीकी डालर के चरम स्तर पर पहुंच गया तथा वर्ष 2009-10 में संतुलित होकर 109.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अदृश्य शेष संबंधी अतिशेषों के अपेक्षाकृत निम्न स्तरों के साथ 2010-11 के प्रथमार्ध में निर्यात वृद्धि की तुलना में सापेक्षतया उच्चतर आयात वृद्धि से अस्थायी चालू खाता घाटा स्तरों की चिंताएं उत्पन्न हुईं। अक्टूबर 2010 में आयात वृद्धि में कमी आने तथा नवम्बर 2010 में निर्यातों के तेज होने से व्यापार घाटा संबंधी चिंताएं समाप्त हो गई हैं; भुगतान संतुलन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो अप्रैल-सितम्बर 2010 के लिए हैं, अदृश्य शेष के स्तरों में संतुलन संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं तथा इनको करीबी रूप से मानीटर किया जाना आवश्यक है।

भुगतान संतुलन घटनाक्रम

अदृश्य प्राप्तियां चालू खाता संबंधी अपचित घाटे की कुंजी हैं; पूंजी प्रवाहों को विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप के बिना सहजता से समाहित किया गया है

1.45 निवल अदृश्य अधिशेष (अदृश्य प्राप्तियों में से भुगतान घटाकर) वर्ष 2009-10 के प्रथमार्ध के दौरान 42.5 बिलियन

अमरीकी डालर की तुलना में 2010-11 के प्रथमार्ध के दौरान 39.1 बिलियन अमरीकी डालर पर निम्नतर था। उच्चतर व्यापार घाटे के साथ युग्मित निम्नतर अदृश्य अधिशेष 2009-10 के प्रथमार्ध में 13.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में चालू खाता घाटे के बढ़कर 27.9 बिलियन अमरीकी डालर होने में परिणामी हुआ। वस्तुओं के व्यापार संकेतकों द्वारा व्यापार घाटे में संतुलन दर्शाने से अन्तरणों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का निष्पादन चालू खाता घाटे के वर्धित स्तरों को वहनीय स्तरों तक लाने में मुख्य कारक है।

1.46 36.7 बिलियन अमरीकी डालर के निवल पूंजी प्रवाह 2010-11 के पूर्वार्ध में उच्चतर थे जबकि वे 2009-10 के पूर्वार्ध में 23.0 बिलियन अमरीकी डालर थे। यह बढ़त पोर्टफोलियो निवेश, मुख्यतः विदेशी संस्थागत निवेशों, अल्पकालिक व्यापार ऋणों और ईसीबी को अंतर्वाहित पूंजी से प्रधानतः संघटित है। तथापि, विशाल बढ़त को भारत में निवल एफडीआई अंतर्वाहों में परिमितता ने पर्याप्ततः प्रति-संतुलित कर दिया। निवल पूंजी अंतर्वाहों में उल्लेखनीय बढ़त के बावजूद, 2010-11 के पूर्वार्ध में प्रारक्षित भंडारों में वृद्धि मुख्य रूप से चालू खाता घाटे के 2009-10 के पूर्वार्ध के स्तरों के दुगुने से अधिक होने के कारण अल्प थी।

विदेशी मुद्रा भंडार

1.47 विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2009 के अंत में 252 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च 2010 के अंत तक 279.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिससे 27.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्ज हुई। कुल वृद्धि में से 13.6 बिलियन अमरीकी डालर मूल्यांकन मुनाफे (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर की गिरावट के कारण) के चलते था तथा शेष 13.5 बिलियन अमरीकी डालर बीओपी के कारण था। वर्तमान राजकोषीय वर्ष में, प्रारक्षित भंडार अप्रैल 2010 के अंत में 279.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर नवंबर 2010 के अंत में 292.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। प्रारक्षित भंडार दिसंबर 2010 के अंत में 297.3 बिलियन अमरीकी डालर के थे जिससे मार्च 2010 के अंत के स्तर से 18.2 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त मुख्यतः मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण दर्ज हुई।

विनिमय दर

1.48 वर्तमान राजकोषीय वर्ष में रुपए की मासिक औसत विनिमय दर अप्रैल तथा दिसंबर 2010 के बीच सामान्यतया 44-47 रुपए प्रति अमरीकी डालर की सीमा के इर्द-गिर्द घटती बढ़ती रही है। रुपए की विनिमय दर में अमरीकी डालर की तुलना में 1.5 प्रतिशत का मूल्यह्रास अप्रैल 2010 में 44.50 रु. प्रति अमरीकी डालर से दिसंबर 2010 में 45.16 रुपए प्रति अमरीकी डालर के रूप में हुआ। रुपया पौंड स्ट्रलिंग (3.2 प्रतिशत) और जापानी येन (12.2 प्रतिशत) जैसी अन्य प्रधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भी इसी अवधि के दौरान लुढ़का।

वैदेशिक ऋण

1.49 भारतीय वैदेशिक ऋण सितंबर 2010 के अंत में 295.8 बिलियन अमरीकी डालर था जो मार्च 2010 के अंत के स्तर की तुलना में 33.5 बिलियन (12.8 प्रतिशत) अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाता है। ऋण में इजाफा अधिकांशतः उच्चतर वाणिज्यिक उधारों, लघुकालिक व्यापार ऋणों और बहुपक्षीय सरकारी उधारों के कारण हुआ। मूल्यांकन प्रभाव से कुल बढ़त में 6.3 बिलियन अमरीकी डालर का इजाफा हुआ। भारत के वैदेशिक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दीर्घकालिक उधारों की प्रबलता निर्दिष्ट करती है जो सितंबर 2010 के अंत में कुल वैदेशिक ऋण के 77.7 प्रतिशत थे।

1.50 अवशोषक सामर्थ्य से अधिक और प्रतिस्पर्द्धितार्थ निहितार्थों से पूंजी प्रवाहों में 2007-08 में प्रोत्कर्ष से मुक्त पूंजीगत खाता, विनिमय दर सुस्थिरता तथा मौद्रिक नीति में आत्मनिर्भरता के तीन असंभव उद्देश्यों को शामिल करने वाले ट्रेड ऑफ के कारण मौद्रिक प्रबंधन जटिल हो गया था। तथापि 2009-10 में और वर्तमान राजकोषीय वर्ष में हुए सुधार से वैदेशिक क्षेत्र मोटे-तौर पर समर्थक बना रहा क्योंकि वर्तमान खातागत घाटों के ऊंचे स्तरों का वित्त प्रबंध बढ़ते पूंजी प्रवाहों द्वारा आसानी से हो गया; हालांकि धारणीयता की चिंताएं प्रकट हो गई थीं। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा बाजारों में नियंत्रित स्थिति के कारण वैदेशिक क्षेत्र मौद्रिक नीति के ढांचे का समर्थक बना रहा।

मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रक घटनाक्रम

मौद्रिक नीति सख्ती के मोड में—मुद्रा स्फीतिकारी दबावों से जूझती हुई और विकास में सहायक, वित्तीय बाजारों में व्यापकतर स्थिरता के साथ प्रतिभूति बाजारों में कुछ उतारचढ़ाव

1.51 आरबीआई ने समायोजन नीति की स्थिति से हटने की प्रक्रिया अक्टूबर 2009 में ही शुरू कर दी थी। इसने अप्रैल 2010 के अपने वार्षिक मौद्रिक नीतिगत विवरण में अनुमानित किया था कि अर्थव्यवस्था ऊर्ध्वमुखी गति से 8.0 प्रतिशत बढ़ेगी और यह कि डब्ल्यूपीआई के अनुसार मुद्रास्फीति मार्च 2011 के अंत तक घटकर 5.5 प्रतिशत के स्तर तक आ जाएगी। नीतिगत विवरण में बजट अनुमान 2010-11 में यथा इंगित निजी क्षेत्र की ऋण संबंधी मांगों और सरकारी उधार की ज़रूरत को 17.0 प्रतिशत के स्थूलमुद्रा (एम₃) विकास के साथ संतुलित करने की कोशिश थी। एससीबी की कुल जमाराशियों के 18.0 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था तथा ऋण बढ़त 20.0 प्रतिशत पर ठहराई गई। चूंकि वर्तमान राजकोषीय वर्ष में बढ़ती खाद्यान्न मुद्रास्फीति के रूप में उत्पन्न आर्थिक घटनाओं और इसके मुद्रास्फीतिकारी अनुमानों को प्रभावित करने के जोखिमों के कारण परिशोधन करना आवश्यक हो गया और उठाए गए अनेक कदमों में प्रधान नीतिगत दरें बढ़ाई गईं। आरबीआई ने नीतिगत दरों को वर्तमान राजकोषीय वर्ष में छह बार

बढ़ाया जिनमें इसकी नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दरें 175 बेसिस प्वाइंट्स तक संचयी रूप में बढ़ाई गईं जिससे यह वर्धित होकर 6.5 प्रतिशत और रिवर्स रिपो दर 225 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई। नकदी प्रारक्षित अनुपात बैंकों की निवल मांग तथा मियादी देयताओं के 6 प्रतिशत पर था।

1.52 आरबीआई ने मौद्रिक नीति विवरण की अपनी अनुवर्ती समीक्षाओं में मार्च 2011 के अंत तक 8.5 प्रतिशत की वृद्धि और 7.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति रहने का परिकलन किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान 28 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार 21.6 प्रतिशत पर प्रारक्षित मुद्रा (एम₀) वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर थी जबकि स्थूल मुद्रा (एम₃) वृद्धि 14 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार 16.6 प्रतिशत पर अल्प रही। वर्षानुवर्ष खाद्यान्नेतर ऋण वृद्धि दिसम्बर, 2010 के अंत तक 24 प्रतिशत अधिक रही, और इससे व्यापक रूप से अनेक क्षेत्र (कृषिगत उछाल से लेकर 3जी तृतीय पीढ़ी, स्पेक्ट्रम विक्रयों और निजी अवसंरचनागत परियोजनाओं तक) वित्तपोषित हुए, जबकि स.घ.उ. में समग्र अनुपात में इजाफा तकरीबन 55 प्रतिशत तक हुआ और इसकी प्रगति जारी है। (परन्तु संरचनात्मक दृष्टि से अभी भी यह क्षमता से काफी न्यून है)

1.53 नीतिगत दरों के कठोर होने और ऋण मांग में उछाल के परिणामस्वरूप नकदी सीमित हो गई। राजकोषीय वर्ष क्रमिक ह्रासमान समावेशन संबंधी नकदी दशाओं के साथ प्रारंभ हुआ; और 3जी स्पेक्ट्रम तथा ब्रांडबैंड वायरलेस नीलामियों और भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्र सरकार के नकदी शेष में परिणामी बढ़त के प्रधान कारण से मई 2010 में अंतर्वेशन विधि की ओर संचलित हो गया। अंतर्वेशन की मात्राएं अक्टूबर तथा नवम्बर, 2010 में बढ़ीं। आरबीआई ने 29 अक्टूबर और 1 नवम्बर, 2010 को विशेष द्वितीय नकदी समायोजन सुविधा पटल की व्यवस्था, 30 अक्टूबर, 2010 को नकदी समायोजन सुविधा के तहत दो दिवसीय विशेष रिपो नीलामी की व्यवस्था, और नकदी समायोजन सुविधा के तहत अतिरिक्त नकदी सहायता का लाभ उठाने के लिए निवल मांग और मियादी देयताओं के 1 प्रतिशत तक एसएलआर के अनुरक्षण में कमी पर दांडिक ब्याज के अधित्याग (30-31 अक्टूबर को) जैसे उपायों को अपनाते हुए ऐसी नकदी की समस्या पर ध्यान देने की कार्रवाई की।

1.54 कतिपय अतिलंघन घटनाओं के साथ मांग मुद्रा दर के एलएएफ सीमा में रहने से मुद्रा बाजार चालू राजकोषीय वर्ष में नियंत्रित स्थितियों में बने रहे। 2010-11 के दौरान संपाश्वर्कृत खंडों की दरें मांग दर के समनुरूप, यद्यपि इससे अल्प रूप में, घटती बढ़ती रहीं। भारत के वित्तीय बाजार 1991 से जारी स्थिर सुधारों के बाद हालिया वर्षों में सुदृढ़ होते रहे। विवेकपूर्ण विनियमों और संस्थाओं ने अर्थव्यवस्था को हालिया वैश्विक वित्तीय आघातों

से संरक्षित किया और इसकी सक्रियता से वर्तमान समुत्थान हो रहा है। घरेलू पूंजी बाजारों ने 2010 में अच्छा निष्पादन दर्शाया, प्राथमिक बाजारों में कीर्तिमान स्तरों का वित्तपोषण हुआ जिसमें विशालतम आईपीओ (कोल इंडिया के लिए) शामिल है, जबकि द्वितीयक बाजारों ने नई ऊंचाइयां छू लीं। कीर्तिमान विदेशी अंतर्विहित पूंजी से बाजार सशक्तीकरण में मदद मिली। जीवन बीमा प्रीमियम के लगभग 26 प्रतिशत तक बढ़ने और अंतर्वेशन के 2000 में (जब बीमा सुधार लागू हुआ) स.घ.उ. के 2.3 प्रतिशत से 2009 में 5.4 प्रतिशत पर दुगुने होने के कारण पेंशनों और बीमा में अधिलाभ हुआ। भविष्य में दोहरी चुनौतियां चल रहे क्रमिक वित्तीय सुधार की इस प्रगति को जारी रखना और इसकी अविच्छिन्न सुरक्षा तथा स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए विनियमों एवं संस्थाओं को आधुनिक बनाना है।

1.55 विगत वर्ष में बैंकिंग जमा राशि संवृद्धि में धीमापन परिलक्षित हुआ क्योंकि वास्तविक ब्याज दरें मंद थी विशेष रूप से अन्य तीव्र सुधारकारी आस्ति बाजारों (स्थावर सम्पदा, स्वर्ण, तथा स्टॉक बाजार) में प्रतिफलों की तुलना में। प्राथमिकता बैंकिंग की पहुंच में पर्याप्त विस्तार कर उसे अपेक्षाकृत बृहत्तर जनसंख्या तक पहुंचाने की है जिससे अधिक बचतों को जुटाने में सहायता मिले, अधिक गहनता का वर्धन किया जा सके तथा मध्यवर्ती अवसरों को अधिक दक्ष एवं कुशल रूप से जुटाया जा सके जिनमें पारम्परिक 'प्राथमिकता' क्षेत्रों के अवसर शामिल हैं। आगामी प्रगति के लिए (1) वित्तीय समावेशन को एक अगले महत्वपूर्ण कदम के रूप में त्वरित किया जाना आवश्यक है; इस संबंध में नवाचारी समाधान किए जाने आवश्यक होंगे; (2) समरूप प्रयास घरेलू पूंजी बाजारों को तथा बैंक भिन्न संस्थाओं की भूमिका को, विशेषतया कारपोरेट बांड तथा ऋण बाजारों में, गहन बनाने के लिए आवश्यक हैं; (3) ऐसे घटनाक्रमों के सम्मिलन में सहायता हेतु राजकोषीय घाटों को तीव्रता से कम किया जाना आवश्यक है; तथा (4) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य विनियामक आमूल सुधार की श्रृंखला आरम्भ की है जिसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण आधुनिक विधान को अद्यतन करना, तथा वृहद्-विवेकपूर्ण सुरक्षोपायों तथा संस्थाओं में सुधार लाना है।

राजकोषीय घटनाक्रम

वर्तमान राजकोषीय वर्ष में वित्तीय समेकन प्रगति के पथ पर अग्रसर; मध्यावधि में प्रक्रिया अभिप्रेरण हेतु सुधार

1.56 स.घ.उ. के अग्रिम अनुमानों में यथा इंगित 2009-10 में अर्थव्यवस्था के समुत्थान के स्पष्ट प्रमाण के साथ 2010-11 के बजट ने उत्प्रेरक उपायों से अंशतः हटते हुए वित्तीय समेकन की राह पुनः फिर पकड़ी। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा 2010-11 के बजट में स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत पर अनुमानित था और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में 2011-12 और

2012-13 के दौरान 4.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत तक और गिरावट निर्दिष्ट की गई। चालू वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों में राजकोषीय स्थिति बजट द्वारा निर्मित समेकन पथ पर मोटे तौर पर बनी रही। वर्तमान राजकोषीय वर्ष में संकटपूर्ण स्तरों पर संवृद्धि के प्रत्यावर्तन, राजस्वों में कायम उछाल और दूरसंचार 3जी/ब्राडबैंड वायरलेस नीलामियों से उत्पन्न हो रहे कर-भिन्न राजस्वों में बजटीकृत वसूली से काफी अधिक वसूली के कारण राजकोषीय घाटे के निर्दिष्ट लक्ष्यों में व्यय के उच्चतर स्तरों की गुंजाइश थी।

1.57 2010-11 के बजट ने स.घ.उ. के प्रति सम्मिलित सार्वजनिक ऋण के अनुपात को 2014-15 तक 68 प्रतिशत तक सीमित करने संबंधी तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुवर्तन प्रास्थिति दस्तावेज में मामलों का विश्लेषण करने के वायदे से किया जिसमें ऐसी कटौती संबंधी कार्य योजना का खुलासा भी होगा। 2010-11 के बजट में इस आशय से की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकारी ऋण विषयक प्रास्थिति पत्र नवम्बर, 2010 में प्रस्तुत किया गया। इस पत्र में स्थिति का सविस्तार विश्लेषण किया गया तथा 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में सामान्य सरकार के लिए स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में समग्र ऋण में घटत की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई। केन्द्रीय ऋण 2014-15 में स.घ.उ. के 43 प्रतिशत पर नीचे आना अनुमानित था जब राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 3.0 प्रतिशत पर सीमित किया जाएगा। राज्य सरकारों के सम्मिलित ऋण के 2009-10 में स.घ.उ. के 24.8 प्रतिशत से घट कर 2014-15 में 23.1 प्रतिशत होने के अनुमान से समेकित सामान्य सरकारी ऋण 2009-10 में स.घ.उ. के 73 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 64.9 प्रतिशत तक हो जाना अनुमानित था। हालिया बजटों में ऐसी सुधारक कार्रवाइयों का सुझाव दिया गया जिनसे यह प्रक्रिया संचालित होगी। इनमें प्रक्रियाधीन कर सुधारों के अतिरिक्त उर्वरकों और पेट्रोलियम तथा लोक व्यय प्रबंधन में इमदादी सुधार शामिल थे।

1.58 चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में राजकोषीय परिणाम सुदृढ़ होने से निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्यों पर व्यय के अपेक्षाकृत उच्च स्तरों की गुंजायश थी। ब०अ० 2010-11 तक पूर्ण वर्ष के लिए परिकल्पित 8.5 प्रतिशत के स्तर की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में कुल व्यय में 11.2 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ राजकोषीय तथा राजस्व घाटे क्रमशः 171,249 करोड़ रुपए और 116,309 करोड़ रुपए आंके गए हैं जो ब०अ० के 44.9 प्रतिशत तथा 42.1 प्रतिशत का संघटन करते हैं। के० सां० सं० के अग्रिम अनुमानों द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित 78,77,947 करोड़ रुपए के मामूली स०घ०उ० के स्तर के साथ स०घ०उ० के प्रति राजकोषीय घाटा अनुपात के संकेतकों के अर्थ में चालू राजकोषीय वर्ष का लक्ष्य 4.8 प्रतिशत रखा गया है तथा राजस्व घाटे के अर्थ में यह 3.5 प्रतिशत रखा गया है।

सामाजिक क्षेत्रक घटनाक्रम

आम आदमी पर संकेन्द्रण तथा प्रमुख विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उच्चतर निधियां; क्रियान्वयन वांछित परिणाम हासिल करने की कुंजी

1.59 वर्ष 2010-11 के लिए बजट में निर्दिष्ट किया गया था कि समावेशी विकास सरकार के लिए एक निष्ठापूर्ण क्रिया है। कानूनी गारंटियों द्वारा समर्थित करके सृजित की गई व्यष्टियों हेतु हकदारिताएं इस आशय का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराती हैं। प्रगामी रूप से सामाजिक क्षेत्रक व्यय बढ़ाया गया है तथा वर्ष 2010-11 में यह कुल योजना परिव्यय का 37 प्रतिशत था। सरकार की क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिकताएं ग्रामीण विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलप्रबंधन एवं स्वच्छता, आवासन, शहरी विकास; अनुसूचित जातियों (एस सी), अनुसूचित जनजातियों (एस टी) तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों (ओबीसी) का कल्याण जैसे क्षेत्रों में निरंतर उच्चतर बजटीय आबंटन के अर्थ में प्रतिबिम्बित होता है। कुल व्यय (आयोजना तथा आयोजना भिन्न) में ग्रामीण विकास सहित सामाजिक सेवाओं पर केन्द्र सरकार के व्यय का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 13.75 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 (ब० अ०) में 19.27 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार सामान्य सरकार (केन्द्र तथा राज्य संयुक्त रूप से) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय ने भी सामाजिक सेवाओं को उच्चतर प्राथमिकता प्रतिबिम्बित करते हुए हालिया वर्षों में वृद्धि दर्शाई है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2005-06 में 21.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 23.8 प्रतिशत हो गया था तथा वर्ष 2010-11 (ब० अ०) में और बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया है।

1.60 रोजगार के क्षेत्र में, देश वैश्विक संकट के प्रतिकूल प्रभाव को सहने में समर्थ रहा है तथा जुलाई 2009 से रोजगार का सृजन कर रहा है जैसाकि श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षणों में सूचित किया गया है। रोजगार में उर्ध्वमुखी रुझान जुलाई 2009 से निरंतर अवलोकित किया गया है। जुलाई से सितम्बर 2010 की तिमाही के दौरान समग्र रोजगार में अनुमानतः 4.35 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले चार त्रैमासिक सर्वेक्षण अवधियों अर्थात् सितम्बर 2009 की तुलना में सितम्बर 2010 के परिणाम निर्दिष्ट करते हैं कि समग्र रोजगार में 12.96 लाख रुपए की वृद्धि हुई है जिसमें से 9.36 लाख की उच्चतम वृद्धि सूचना प्रौद्योगिकी/व्यवसाय प्रक्रिया बहिष्प्रेतण (बीपीओ) में हुई है जिसके पश्चात वस्त्र क्षेत्र में 0.79 लाख की वृद्धि, धातु क्षेत्र में 0.99 लाख की वृद्धि, आटोमोबाईल में 1.15 लाख की वृद्धि तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में 0.39 लाख की वृद्धि हुई है।

1.61 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो अभूतपूर्व पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, के तहत प्रगति संतोषजनक रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के तहत 5.26 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था

जबकि वर्ष 2008-09 में रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 4.51 करोड़ थी। वर्ष 2010-11 के दौरान दिसम्बर 2010 तक लगभग 4.10 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत सृजित 145 करोड़ श्रम दिवसों में से 23 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत श्रम दिवस क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए सृजित किए गए थे तथा कुल श्रम दिवसों का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के पक्ष में सृजित किया गया था।

1.62 6-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए राज्यों की सहभागिता में क्रियान्वित किए जा रहे सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) में अन्य बातों के अलावा निम्न का प्रयास किया गया है सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन; शिक्षा गारंटी केन्द्रों (ईजीसी), वैकल्पिक विद्यालयों, "वापस विद्यालय" कैम्पों की वर्ष 2005 तक स्थापना, वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक चरण तक सभी बच्चों का प्रतिधारण; प्रतिधारण तथा अभिगम के साथ नामांकन में बालक-बालिका तथा सामाजिक श्रेणी अंतरों को पाटना और यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अवस्था पर बच्चों के अधिगम उपलब्धि स्तर में महत्वपूर्ण वर्धन हो। सितम्बर 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्धि में 309727 नए विद्यालय, 254935 विद्यालय भवनों का निर्माण, 1166868 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, 190961 पेयजल सुविधाओं, 347857 शौचालयों का निर्माण, 8.70 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति तथा, 11.13 लाख अध्यापकों की नियुक्ति शामिल है। लगभग 14.02 लाख अध्यापकों ने इस कार्यक्रम के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। एसएसए के तहत किए गए उपायों के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण अपचयन हुआ है।

1.63 निर्धन व्यक्तियों तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर बल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को सुगम्य, वहनीय तथा जवाबदेही उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। 18 राज्यों जिनमें 8 अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्य (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा तथा राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं, पर विशेष संकेन्द्रण के साथ इसे सम्पूर्ण देश में प्रचालनरत किया जा रहा है। सितम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार एनआरएचएम के तहत उपलब्धियों में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं-8.33 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का चयन, 1572 विशेषज्ञों, 8284 एमबीबीएस डाक्टरों, 26734 स्टॉफ नर्सों, 53552 सहायक नर्स मिडवाइव्स (धात्री) (एएनएम), 18272 अर्ध चिकित्सकों का संविदा आधार पर नियोजन तथा कुल 16338 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एपीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) तथा अन्य उप जिला सुविधाओं को 24 x 7 आधार पर प्रचालनरत किया गया।

1.64 हालांकि सरकार ने निर्धनतारोधी कार्यक्रमों तथा रोजगार सृजन योजनाओं के लिए बजटीय आवंटनों में सचेत रूप से सोच समझ कर भारी वृद्धि की है, परिदाय प्रक्रम को समर्थित करना तथा सुप्रवाही बनाना आवश्यक है ताकि इन कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुकर बनाया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवंटन उत्पादन में परिणामी हों तथा उत्पादन के सही परिणाम निकलें, सरकार द्वारा परिणामी बजट तथा भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना के लिए की गई पहलें सही दिशा में उठाए गए कदम हैं।

जलवायु परिवर्तन

1.65 हरित गृह गैस (जीएचजी) निम्नांकों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर गहन राजनैतिक ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक देशों का कुल निम्नाव विशालतम है तथा वैश्विक जीएचजी निम्नांकों में भारत का हिस्सा सापेक्षतया लघु है। जलवायु परिवर्तनों के भारत के लिए विशाल निहितार्थ हैं। विभिन्न अध्ययन निर्दिष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कृषि, जल, प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली, जैव विविधता तथा स्वास्थ्य हैं। यह एकदम ऐसे समय पर घटित हो रहा है जब इसके समक्ष अत्यधिक विशाल विकास आवश्यकताएं हैं। एक हालिया भारत-विशिष्ट रिपोर्ट में प्रभावों की चेतावनी दी गई है जैसे समुद्र स्तर का बढ़ना, चक्रवात सघनता में वृद्धि, वर्षापोषित फसलों में अपचित फसल पैदावार, पशुधन पर दबाव, दुग्ध उत्पादकता में कमी, वर्धनशील बाढ़ प्रकोप तथा मलेरिया का फैलना।

1.66 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय (1994 में प्रवृत्त अभिसमय) का लक्ष्य निम्नांकों को घटाकर स्थिर वहनीय स्तरों तक लाना तथा विकासशील देशों को वित्त तथा प्रौद्योगिकी के अर्थ में सहायता उपलब्ध करना था। अभिसमय के परिणामस्वरूप वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकाल अंगीकृत किया गया। पक्षकार सम्मेलन (सीओपी) जो अभिसमय का सर्वोच्च संगठन है, की बैठक हर वर्ष होती है; दिसम्बर 2007 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 13वें सीओपी में बाली कार्य योजना नामक एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके पश्चात् दिसम्बर 2009 में 'कोपनहेगन एकार्ड' प्रवृत्त हुआ। 29 नवम्बर-11 दिसम्बर 2010 के दौरान कनकन में आयोजित सर्वाधिक हालिया वार्ताएं उपशमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी तथा वित्त समाहित आगामी निर्णयों में परिणामी हुई हैं। कनकन करारों को व्यापक रूप से सौम्य, संतुलित, प्रगतिशील तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया में आस्था और विश्वास की पुष्टि के रूप में देखा जाता है। कनकन में विकासशील देशों के अनुकूलन एवं उपशमन कार्यों की सहायतार्थ वैश्विक स्तर पर एक हरित जलवायु कोष, एक प्रौद्योगिकी प्रक्रम तथा एक अनुकूलन समिति का गठन करने के निर्णय लिए गए थे।

1.67 जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने का भारत का निश्चय वर्ष 2016 तक ऊर्जा किफायत में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने के इसके निर्दिष्टात्मक लक्ष्य से स्पष्ट है, इसे अब सक्रिय नीतियों के जरिए वर्ष 2020 तक 2005 के स्तर के 20-25 प्रतिशत द्वारा स.घ.उ. की निम्नाव गहनता को कम करने के अंतर्देशीय उपशमन लक्ष्य द्वारा अनुपूरित किया गया है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपेक्षित संसाधन विभिन्न स्रोतों से जुटाए जाने आवश्यक होंगे। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख स्तम्भ के रूप में निम्न कार्बन कार्य नीति संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं। दूसरे, भारत ऊर्जा ईंधन मिश्र को विविधीकृत करने के लिए सचेत उपाय कर रहा है, जैसे वर्ष 2022 तक 20000 मेगावाट की सौर विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करना, ऊर्जा मिश्र में नाभिकीय विद्युत के 3 प्रतिशत के वर्तमान अंश को अगले दशक में दोगुना करना, ऊर्जा किफायत प्रेरित करने के लिए एक प्रमुख बाजारधारित कार्यक्रम सुव्यवस्थित करना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान तथा विकास का निधियन करने के लिए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर अधिरोपित करना, यद्यपि कोयला हमारी भावी ऊर्जा कार्यनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखेगा तथा विद्युत उत्पादन में आक्रामक रूप से प्राकृतिक गैस के प्रयोग का विस्तार करना। तीसरे, भारत वानिकी के लिए आक्रामक कार्यनीतियों का परिशीलन करता आ रहा है तथा इसने हमारे तट के समीपवर्ती सुभेद्य क्षेत्रों में रह रहे हमारे देश के 300 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा सामना की जा रही अनुकूलन चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन संबंधी एक प्रमुख नए कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। इसके अतिरिक्त, भारत अनुकूलन के लिए निर्णीत रूप से तत्पर कई तत्वों वाली अनेक केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इस समीक्षा के लिए संचालित एक प्रक्रिया सुझाती है कि इन अनुकूलन उन्मुखी योजनाओं पर भारत का व्यय वर्ष 2000-01 में स.घ.उ. के 1.45 प्रतिशत से प्रभावशाली रूप से बढ़कर वर्ष 2009-10 के दौरान 2.82 प्रतिशत हो गया है। भारत ने जून 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी एक राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा भी की है जिसमें सौर ऊर्जा, वर्धित ऊर्जा किफायत, स्थायी कृषि, स्थायी वासस्थल, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी प्रणाली, वनावरण को बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक जानकारी के क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल है। राज्य कार्य योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

1.68 जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों में अंततः लागतें शामिल हैं। अनुकूलन तथा उपशमन योजनाओं एवं परियोजनाओं को अभिकल्पित तथा क्रियान्वित करने के लिए भारत जैसे देशों के लिए निधियन महत्वपूर्ण है। कनकन करारों का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष 'तीव्र आरंभ वित्त', दीर्घावधिक वित्त तथा 'हरित जलवायु कोष' संबंधी निर्णय है। लगभग 30 बिलियन अमरीकी डालर से एक 'हरित जलवायु कोष' की स्थापना 2010-12 की अवधि के लिए करने का निर्णय लिया

गया था जिसकी सहायताार्थ एक स्वतंत्र सचिवालय होगा तथा इसकी अभिकल्पना 40 सदस्यों -विकसित देशों से 15 तथा विकासशील देशों से 25-वाली एक अंतर्वर्ती समिति द्वारा की जाएगी, इसने विकासशील देशों की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए "दीर्घावधिक वित्त" के रूप में वर्ष 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष संयुक्त रूप से जुटाने के लक्ष्य को भी स्वीकार किया। 100 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य विकसित देशों के स.घ.उ. के 1.5 प्रतिशत के निर्धारित अंशदानों के लिए विकासशील देशों की मांग से कम पड़ता है। इसके अतिरिक्त, विकासशील देश प्रमुख स्रोत के रूप में सरकारी निधियों पर जोर दे रहे थे जबकि कनकन करार में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि विकसित देशों द्वारा निधियां किस प्रकार जुटाई जाएंगी। इस संदर्भ में, भारत की पहलें सफल होंगी यदि इक्विटी के ठोस सिद्धांतों तथा आम लेकिन सुभिन्न उत्तरदायित्वों पर निर्मित कार्यों का वैश्विक ढांचा प्रभावपूर्ण तथा समर्थनकारी है जिसमें प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण प्रयास शामिल हैं।

संभावनाएं, अल्पावधिक तथा मध्यमावधिक

1.69 विगत पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था के निष्पादन तथा विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तियों के अंतर्हित रूझानों के विश्लेषण के आधार पर, भारत के वास्तविक स.घ.उ. में वर्ष 2011-12 में 9 प्रतिशत (+/-0.25) की वृद्धि होने की आशा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2005-06 से लगातार तीन निरंतर वर्षों के लिए 9 प्रतिशत से अधिक की संवृद्धि हुई थी। अतः अर्थव्यवस्था के अगले वर्ष तक संकट पूर्व के संवृद्धि स्तरों तक प्रतिवर्तित हो जाने की आशा है। देश की बचतें तथा निवेश दरें वर्ष 2008-09 के दौरान कुछ कम हो गई थी जिसका कारण आर्थिक गिरावट के उपचार के रूप में खपत को प्रोत्साहित करने का सरकार द्वारा लिया गया सोचा समझा निर्णय है। बचत तथा निवेशों संबंधी अद्यतन आंकड़े, जो वर्ष 2009-10 से संबंधित हैं, दर्शाते हैं कि इन दरों में क्रमावर्तन हुआ है। वर्ष 2009-10 में बचत दर विगत वर्ष की 32.3 प्रतिशत की दर से बढ़कर 33.7 प्रतिशत पर थी, तथा निवेश दर में भी बढ़ोत्तरी हुई है तथा यह 36.5 प्रतिशत है। भारत का वर्धनात्मक पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) ग्यारहवीं योजना के लिए 4.1 होने का अनुमान है। यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था में अभी भी आधिक्य क्षमता है, ये दो संकेतक 9 प्रतिशत से मामूली सी कम स.घ.उ. संवृद्धि के अनुमान में परिणामी होते हैं। चूंकि बचतें और निवेश अब एक सकारात्मक संवेग दर्शाते हैं तथा सरकार प्रेरण पैकेज से क्रमिक निकासी को क्रियान्वित कर रही है, बचत तथा निवेश दरों में आगे और वृद्धि होने की संभावना है। अतः यह आशा है कि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि वर्ष 2011-12 में 9 प्रतिशत के स्तर को पार कर जाएगी।

1.70 संवृद्धि पूर्वानुमान तथा सामान्यतः जीवन में लगाए गए सभी पूर्वानुमान, चाहे उन्हें कितनी भी सावधानी से अनुमानित

किया गया हो, त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। मौसम दशाओं में तीव्र हास अथवा कच्चे पेट्रोलियम की कीमत में अनानुपातिक उछाल अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि में परिणामी हो सकता है। समान रूप से, अनुकूल दिशा में इन परिवर्तियों का अकस्मात् संचलन वृद्धि दर को बढ़ावा दे सकता है। ऊपर अभी उल्लिखित कारकों के अलावा, यह उल्लेखनीय है कि यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक दशाओं पर अनिश्चितता की कतिपय प्रमात्रा का प्रवृत्त रहना जारी है। जापान ने भी अपनी दीर्घ मंदी से सुधार के स्पष्ट चिन्ह अभी नहीं दर्शाए हैं। इन औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में से काफी राष्ट्रों में राजकोषीय स्थिति तथा सावरेन ऋण के स्तर भी कुछ कुछ कमजोर स्थिति में हैं। जबकि भारत का बढ़ता व्यापार तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ वित्तीय संबंधन औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में अधोमुखी क्रमावर्तन के विरुद्ध कुछ संरक्षा उपलब्ध कराते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकृत राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। अतः किसी भी प्रमुख औद्योगिकीकृत राष्ट्र में गंभीर संकट की स्थिति में भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि प्रत्याशा यह है कि औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में गंभीर अधोमुखी क्रमावर्तन नहीं आएगा; अथवा अधिक सटीक रूप से एक द्वितीय अधोमुखी हास एक अत्यंत निम्न संभावना वाली घटना है। अतः यह प्रत्याशा निर्दिष्ट होती है कि भारत की संवृद्धि 9 प्रतिशत है।

1.71 मध्यमावधि से आगे बढ़कर दीर्घावधि में देखते हुए, प्रत्याशा यह है कि भारत के आर्थिक विकास की गति में और अधिक तेजी आएगी। इस प्रत्याशा के दो कारण हैं। बचत तथा निवेश दरों में संवेग को देखते हुए तथा साथ ही इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अभी चरम सीमा तक पहुंचना है तथा यह साक्ष्य है कि भारत की कार्यशील आय वाली जनसंख्या, विशेषतः त्रिशंत और चत्वरिशंत की आयु के लोगों के लिए बचत दर अनानुपातिक रूप से उच्च है, आईसीओआर के प्रति निवेश का अनुपात अगले आधे से एक दशक के बीच बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना निर्माण में लगाया जाने वाला निवेश का भाग बढ़ रहा है। स्थायी तथा समावेशी विकास के लिए अवसंरचना का महत्व अब सुस्वीकृत है तथा योजना आयोग बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बहुत अधिक बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।

1.72 यह ज्ञात है कि जब कोई अर्थव्यवस्था एक बार अपनी क्षमता के सन्निकट प्रचालन करना आरम्भ कर देती है तो बचत और निवेश दरें फिर स.घ.उ. संवृद्धि की इतनी अधिक प्रभावी संचालक नहीं रहती। तब संवृद्धि काफी अधिक कौशल विकास तथा देश में नवाचार क्रियाकलाप पर निर्भर करती है। सौभाग्यवश, भारत में इसके बारे में जागरूकता है तथा कौशल विकास और मानव पूंजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक पहलों तथा बजटीय आबंटन के रूप में प्रयास किए जाने जारी हैं। किसी राष्ट्र में नवाचार क्रियाकलाप को मापना कठिन है किन्तु पेटेंट करने की क्रिया द्वारा अधिनिर्णय करने पर भारत में अनुसंधान तथा

22 आर्थिक समीक्षा 2010-11

नवाचार में बढ़ोत्तरी हुई प्रतीत होती है। पारम्परिक रूप से पेटेंट आवेदन पत्र बहुत कम तथा काफी अंतरालों पर होते हैं। तथापि, इसमें विगत कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में, 17,466 पेटेंट दायर किए गए थे तथा 1911 पेटेंट प्रदान किए गए थे। इसके विपरीत 2008-09 में 36812 पेटेंट दायर किए गए थे तथा 16,061 पेटेंट प्रदान किए गए थे। विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अनुसंधान केन्द्रों सहित भारत की उच्चतर शिक्षा

प्रणाली को बढ़ावा देने की भी पहलें की गई हैं। यह आशा है कि इन पहलों में तेजी आएगी तथा ये आर्थिक वृद्धि के चालक के रूप में बचत दर की हासिल होती शक्ति को पूरा करने में कहीं अधिक आगे बढ़ जाएंगी। परिणामस्वरूप, अगले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि विगत किसी भी समय हासिल वृद्धि से तीव्रतर हो जाएगी तथा साथ ही यह अगले दो वर्षों में वृद्धि से भी अधिक तीव्रतर हो जाएगी।